सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 184, नई दिल्ली

शनिवार, 16 सितम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

ऊँचाई पर वही पहुँचते है, जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते है।

गडकरी का सुझाव : ऑटो डीलरों को भी वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं खोलनी चाहिए, ऐसे बढ़ेगी बिक्री

संजय बाटला

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि पूरे भारत में ऑटोमोबाइल डीलरों को भी वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं खोलनी चाहिए। पीटीआई की रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिली है। पांचवें ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव में बोलते हुए, गडकरी ने कथित तौर पर कहा कि भारत सरकार एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर रही है, और उस रणनीति का पालन करते हुए, सरकार डीलरों को वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं शुरू करने की अनुमति देगी।

पहले से हैं इनके व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर

मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स सहित कुछ ऑटो निर्माताओं ने पहले ही देश भर में अपने व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र) शुरू कर दिए हैं। हालांकि, देशभर में वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों की संख्या पुराने वाहनों की संख्या की तुलना में बहुत कम है जिन्हें स्क्रैप करने की जरूरत है। ज्यादा वाहन स्क्रैपिंग केंद्र शुरू होने से प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसलिए, गडकरी ने कहा है कि ऑटोमोबाइल डीलरों को ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए।

बढ़ेगी वाहनों की बिक्री

मंत्री जी ने आगे कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से ऑटोमोबाइल की बिक्री 18 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

उनका मानना है कि कबाड़ हुए वाहनों से मिले कच्चे माल का इस्तेमाल करने से कच्चे माल की खरीद पर 33 प्रतिशत लागत की बचत होगी और नए वाहनों की बिक्री में 18-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनका मानना है कि यह नीति भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरिंग केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

कम होगा प्रदूषण

अगस्त 2021 में पहली बार पेश की गई वाहन स्क्रैपेज नीति, वाहन प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए पूरे भारत में पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर केंद्रित है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुराने वाहन नए मॉडलों की तुलना में पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषित करते हैं। इस नीति का मकसद 20 वर्ष से ज्यादा पुरानी निजी कारों और 15 वर्ष से ज्यादा पुराने कमर्शियल व्हीकल्स (वाणिज्यिक वाहनों) का पंजीकरण रद्द करना है।

कैसा होगा इकोसिस्टम

पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने और उन्हें भारतीय सड़कों पर मॉडर्न और नए वाहनों से बदलने के सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के तहत, प्राथमिक लक्ष्य देश भर में कम कार्बन फुटप्रिंट हासिल करने के लिए अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना है।

इस साल अप्रैल में लागू की गई वाहन स्क्रैपेज नीति ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) के जरिए भारी वाणिज्यिक वाहनों (एचसीवी) की फिटनेस टेस्टिंग को अनिवार्य बनाती है। अन्य प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों (सीवी) और निजी वाहनों (पीवी) के लिए, फिटनेस परीक्षण जून 2024 से शुरू होकर सिर्फ एटीएस के जरिए आयोजित किया जाएगा। यदि कोई वाहन फिटनेस परीक्षण में नाकाम रहता है, तो इसे ईएलवी (एंड-ऑफ-लाइफ) के रूप में परिभाषित किया जाएगा। जिसके बाद वाहन को स्क्रैप कर दिया जाएगा।

नीचे मेट्रो और ऊपर दौड़ेगी रैपिड रेल

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की रोक-थाम और सड़कों से वाहनों की भीड़ कम करने के लिए बनाए जा रहे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का पुल तैयार हो गया है। दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन के ऊपर से बने पुल से दिल्लीवासियों को ट्रैफिक की समस्या से नहीं जूझना होगा। यह पुल न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक लगभग 20 मीटर की ऊंचाई पर दिल्ली मेट्रो के कॉरिडोर को पार कर रहा है। मेट्रो रेल के ऊपर इतनी ऊंचाई पर पहली बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने पुल तैयार किया है। इंजीनियरिंग के नजरिए इसे इसे बेहद अहम माना जा रहा है।

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए इस हिस्से के वायाडक्ट का अधिकतम निर्माण कार्य रात्रि के समय किया गया। लॉन्चिंग गेंट्री की सहायता से गर्डर के सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम किया गया और समय से इसका निर्माण कर लिया गया है। इस कार्य में एनसीआरटीसी को डीएमआरसी का पूरा सहयोग मिला है। इसके अंतर्गत यात्रियों की सुगम और निर्बाध यात्रा के लिए आरआरटीएस स्टेशनों की योजना रणनीतिक रूप से इस प्रकार बनाई गई है कि इन्हें मौजूदा सार्वजनिक परिवहन साधनों के जितना करीब संभव हो बनाया जाए और इनमें आपस में कनेक्टिविटी प्रदान की जाए।

नोएडा से आने वाले यात्रियों को होगा फायदा

न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन पर बड़ी संख्या

में यात्री नोएडा से आते हैं। मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन के माध्यम से भविष्य में ये यात्री न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन पहुंचकर सीधी रैपिड रेल पकड़ कर मेरठ या दिल्ली की ओर यात्रा कर सकेंगे।

90 मीटर लंबा एफओबी भी

न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन को न्यू अशोक नगर के मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगभग 90 मीटर लंबा और करीब छह मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। यह मेट्रो के कॉनकोर्स लेवल पर कनेक्ट होगा। इस फुटओवर की ऊंचाई ज़मीन से करीब आठ मीटर होगी। दिल्ली में एलिवेटेड सेक्शन के लिए अब तक पांच किलोमीटर से ज्यादा लंबे वायाडक्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पिलर निर्माण का भी 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। एनसीआरटीसी का लक्ष्य है कि जून 2025 तक पूरे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को परिचालित किया जाए।

टेस्ला की भारत में कारोबार लगाने में दिलचस्पी के बीच, भारत ला सकता है नई ईवी नीति

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेशी ईवी निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए एक नई और व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की योजना बना रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार स्थानीय मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत के ईवी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से ज्यादा निवेश की उम्मीद कर रही है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता Tesla (टेस्ला) नए प्लांट के साथ-साथ कंपोनेंट्स में निवेश के प्रस्तावों के साथ भारत में एंट्री करने की योजना बना रही है।

भारत के बड़े बाजार पर कब्जा करने की कोशिश में, टेस्ला नई कार पर जोर दे रही है, जो ईवी निर्माता की अब तक की सबसे सस्ती कार होगी। इसकी कीमत टेस्ला के मौजूदा एंट्री-लेवल मॉडल Model 3 (मॉडल 3) से कम होने की उम्मीद है, जो लगभग 24,000 डॉलर (लगभग 20 लाख रुपये) हो सकती है। इसे भारतीय बाजार और निर्यात के लिए भारत में ही बनाया जाएगा। हाल ही में, एक उच्च-स्तरीय टेस्ला टीम भारत सरकार के अधिकारियों के साथ अपनी निवेश योजना पर चर्चा करने के लिए भारत आई थी। इसके बाद पीएम के अमेरिकी दौरे के दौरान टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भी एक नए प्लांट सहित

भारत में निवेश करने में दिलचस्पी जताई है।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अगर ईवी निर्माता देश में निवेश के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो भारत विदेशी इलेक्ट्रिक कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) कम करने पर विचार कर रहा है। यह केंद्र की आगामी ईवी नीति का हिस्सा हो सकता है। पीयूष गोयल ने कहा कि नई नीति सभी हितधारकों से चर्चा के बाद तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा, "हम एक नीति लेकर आएंगे। जैसे ही हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन मिलेगा, हम नई प्रौद्योगिकियों के पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के फल का आनंद लेना शुरू कर देंगे।

भारत में टेस्ला की दिलचस्पी लगभग एक साल बाद आई है जब इसके सीईओ ने आयात शुल्क कम नहीं करने के केंद्र के रुख के कारण योजनाओं को व्यावहारिक रूप से रद्द कर दिया था। केंद्र का रुख रहा है कि जब तक ईवी निर्माता निवेश या स्थानीय उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध न हो, तब तक शुल्क में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। टेस्ला के रुख में यह तीव्र उलटफेर काफी अहम है क्योंकि टेस्ला ने केंद्र से कई बार टैक्स को कम करने पर विचार करने का आग्रह किया था। भारत में टेस्ला की एंट्री से अन्य वैश्विक ईवी निर्माताओं के लिए यहां निवेश की योजना बनाने के रास्ते खुल सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- क्या ड्राइविंग लाइसेंस के मुद्दे पर कानून में बदलाव की जरूरत है

को कानूनी रूप से चलाने का हकदार है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि ये नीतिगत मुद्दे हैं जो लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करते हैं। पीठ ने कहा कि सरकार को इस मामले पर ₹नया सिरे से विचार₹ करने की जरूरत है और कहा कि इसे नीतिगत स्तर पर उठाया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने केंद्र से दो महीने के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने और किए गए निर्णय के बारे में उसे अवगत कराने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के किसी भी व्याख्या को सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन के अन्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के वैध चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने पहले ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से इस कानूनी सवाल पर सहायता मांगी थी कि क्या एक व्यक्ति जो एक हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, क्या वह किसी विशेष वजन के परिवहन वाहन को कानूनी रूप से चलाने का हकदार है। संविधान पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थिति जानना आवश्यक होगा, क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में, शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को केंद्र ने स्वीकार कर लिया है और नियमों को इस निर्णय के अनुरूप संशोधित किया गया है। मुकुंद देवांगन मामले में, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि परिवहन वाहन, जिनका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है, को एलएमवी की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है।

पीठ ने कहा, ₹देश भर में लाखों ड्राइवर हैं जो देवांगन फैसले के आधार पर काम कर रहे हैं। यह एक संवैधानिक मुद्दा नहीं है। यह एक शुद्ध वैधानिक मुद्दा है।₹ इस पीठ में न्यायमूर्ति ह्रषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मितल और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

पीठ ने कहा, ₹यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, बल्कि कानून के सामाजिक प्रभाव का भी सवाल है... सड़क सुरक्षा को कानून के सामाजिक उद्देश्य के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और आपको यह देखना होगा कि क्या इससे गंभीर कठिनाइयां पैदा होती हैं। हम संविधान पीठ में सामाजिक नीति के मुद्दों का फैसला नहीं कर सकते।₹

गुरुग्राम-दिल्ली-नोएडा के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग

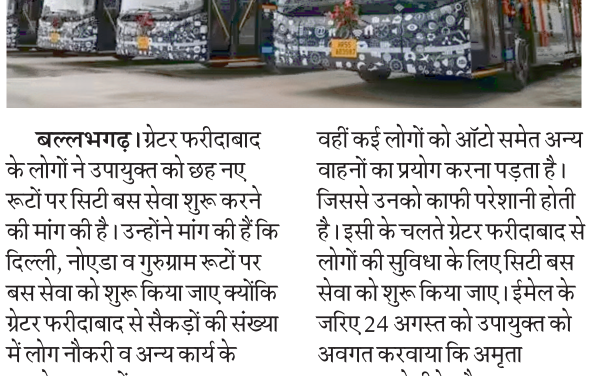

बल्लभगढ़। ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों ने उपायुक्त को छह नए रूटों पर सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने मांग की हैं कि दिल्ली, नोएडा व गुरुग्राम रूटों पर बस सेवा को शुरू किया जाए क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद से सैकड़ों की संख्या में लोग नौकरी व अन्य कार्य के चलते इन जगहों पर आना-जाना पड़ता है। जिसके बाद उपायुक्त द्वारा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए), स्मार्ट सिटी और रोडवेज महाप्रबंधक को पत्र लिखकर बस सेवा शुरू करने के बारे में अवगत करवाया है।

ग्रेटर फरीदाबाद स्थित बीपीटीपी पार्कलैंड निवासी सुमेर चंद अत्री, जितेंद्र व मोहित ने बताया कि ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 75 से सेक्टर 89 तक हजारों लोग रहते है। जिसमें से सैकड़ों की संख्या में नौकरी के लिए दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम को आते जाते है। उन लोगों को इन जगहों पर आने जाने के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं कई लोगों को ऑटो समेत अन्य वाहनों का प्रयोग करना पड़ता है। जिससे उनको काफी परेशानी होती है। इसी के चलते ग्रेटर फरीदाबाद से लोगों की सुविधा के लिए सिटी बस सेवा को शुरू किया जाए। ईमेल के जरिए 24 अगस्त को उपायुक्त को अवगत करवाया कि अमृता अस्पताल से बीके चौक, अमृता अस्पताल से राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, तिगांव से एनआईटी बस स्टैंड , पुरी प्राणायाम से सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन, ग्रेटर फरीदाबाद से गुरुग्राम और ग्रेटर फरीदाबाद से नोएडा के लिए शुरू की जाए। इसको लेकर रूट मैप को बनाकर उपायुक्त विक्रम सिंह को अवगत करवाया। जिसके चलते उपायुक्त विक्रम सिंह ने एफएमडीए, स्मार्ट सिटी और रोडवेज महाप्रबंधक को पत्र लिखकर अवगत करवाया है। इन रूटों पर बस सेवा शुरु होने के बाद ग्रेटर फरीदाबाद सोसायटी के लोगों के साथ साथ गांव के लोगों को भी फायदा मिलेगा।

सरकार ने रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए जारी किया बजट

नई दिल्ली। दिल्ली की गाजियाबाद व मेरठ से कनेक्टिविटी को विस्तार देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सार्थक कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 1306 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली, गाजियाबाद व मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को विकसित करने के लिए योगी सरकार द्वारा 956 करोड़ रुपए की अवशेष धनराशि में से 350 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटन को स्वीकृति मिल गई है। इस राज्यांश के जारी होने से परियोजना के अंतर्गत लंबित कार्यों को अब गति मिल सकेगी। विशेषतौर पर गाजियाबाद व मेरठ में परियोजना के अंतर्गत प्राविधानित कार्यों को अब नए सिरे से रफ्तार मिलेगी। योगी सरकार द्वारा इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के प्रबंध निदेशक को धन आवंटन संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार की मंशा प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों की दिल्ली से कनेक्टिविटी सुधारने की रही है और मौजूदा प्रयास को भी इसी संदर्भ में एक सार्थक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली-मेरठ रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) एक सेमी हाई स्पीड रेल कोरिडोर है। इसका अभी निर्माण चल रहा है। यह कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। रैपिड एक्स प्रोजेक्ट के तहत प्लान किया गया यह तीन रैपिड रेल कॉरिडोर्स में से एक है। पूर्ण होने पर यह देश का अपनी तरह का पहला रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट होगा। फिलहाल, इस परियोजना के तहत फेज वन स्टेज का कार्य हो रहा है। 82.15 किमी लंबी इस परियोजना की 8 मार्च 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई थी और माना जा रहा है कि वर्ष 2025 तक इसकी शुरूआत हो सकती है। परियोजना को मूर्त रूप देने का दायित्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को सौंपा गया है।

ट्रैकिंग और महिला सुरक्षा के नाम पर जेंडर सेंसेटाइज़ेशन क्लास को लागू करने को लेकर सेक्रेटरी कम कमिश्नर को लिखा पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सेक्रेटरी कम कमिश्नर आशीष कुंद्रा, परिवहन विभाग रा० रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार से 'ऑटो परिवार चैरिटेबल वेलफेयर परिवार' ने पत्र लिखकर मांग की है। उन्होंने पूछा कि दिल्ली राज्य की तमाम ऑटो यूनियंस और ऑटो चालक आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। उम्मीद है कि ट्रैकिंग और महिला सुरक्षा के नाम पर जेंडर सेंसेटाइज़ेशन क्लास को लागू करने पर उचित जवाब देते हुए केंद्र सरकार द्वारा 28 नवम्बर 2016 को जारी गजट नोटिफिकेशन GSR 1095 E जारी कर सभी पब्लिक विवादों का अंत करेंगे।

1. जीपीएस ट्रैकिंग,

सर्विस वेहिकल्स के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम व इमरजेंसी बटन (पानिक कंट्रोल बटना लगाना अनिवार्य किया गया था।

इन नियमो को 1 अप्रैल 2018 से लागू होना था। इस गजट में ही दुपहिया वाहनो, तिपहिया वाहनों ओर बैटरी रिक्शा को उपरोक्त नियमो से मुक्त कर दिया गया था।

तो अभी तक दिल्ली सरकार किसके फायदे के लिए और क्यों जीपीएस ट्रैकिंग को लागू करना चाहती है ? जबकि आपके पास पैनिक कंट्रोल के इस्तेमाल पर पात्रियों की सहायता की कोई व्यवस्था ही नहीं है। न ही दिल्ली पुलिस के पास ऑटो टैक्सी के पैनिक कंट्रोल के इस्तेमाल पर सवरियो की सहायता का कोई इंतज़ाम है।

दिल्ली में लगभग 1 लाख ऑटो रिक्शा है और आपने सभी को एक दम से धमकी भरा मेसेज भेज आतंकित कर दिया है जबकि न तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ओर न ही डिम्प्ट्स के पास दिल्ली राज्य के तमाम लाखो ऑटो टैक्सियों ग्रामीण सेवा आदि वाहनों को जीपीएस सर्विस देने में सक्षम है।

इस ट्रैकिंग से न तो ऑटो चालकों को न ही सवरियो को ओर न ही परिवहन विभाग को कोई फायदा है। दिल्ली में अवैध तरीके से चलने वाली बाइक्स बैटरी रिक्शा टैक्सीयां बसें डग्गामार वाहनों की भरमार है। दिल्ली राज्य में जब तक अवैध वाहनों की भरमार है, जब तक बिना परमिट या किसी अन्य के परमिट पर किसी अन्य चालक के द्वारा वाहन चलाये जाते है या सवरियो को ढोया जाता है तब तक इस प्रकार की सेवा से कुछ फायदा नही मिल सकता इस लिए दिल्ली राज्य की तमाम ऑटो यूनियंस आपसे मांग करती हैं कि दिल्ली के ऑटो चालकों पर जबरन व्हीकल ट्रैकिंग को न थोपा जाए।

2. जेंडर सेंसेटाइज़ेशन क्लास,

जेंडर सेंसेटाइज़ेशन किसके लिए जरूरी है परिवहन वाहन चालकों के लिए या ट्रेनिंग करवाने वाली संस्था के लिए ?

निर्भया कांड के बाद ऑटो टैक्सी ओर परिवहन वाहन चालकों को शायद इसके लिए दोषी मान लिया गया और ज़बरन ट्रेनिग क्लास लागू कर अपना पल्ला झाड़ लिया लगता है और शायद सरकार को लगता है कि इस जेंडर सेंसेटाइज़ेशन क्लास को लगाने से ही निर्भया को इंसाफ मिल गया है. क्या दिल्ली में चालक होने का मतलब व्यभिचारी होता है ?

क्या दिल्ली के सभी चालकों के घरों में बहन बेटियां नही होती ? क्या परिवहन विभाग ने हम ऑटो टैक्सी चालकों को जीवनभर के लिए दोषी मान लिया है ? कि जब तक ऑटो टैक्सी या परिवहन वाहन चलाएंगे उन्हें यह सज़ा दी जायेगी ?

दिल्ली के तमाम चालक ओर उनके प्रतिनिधि जानना चाहते है कि चालको की ओर से महिला उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज किए गए है ?

हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि दिल्ली राज्य के ऑटो टैक्सी परिवहन वाहन चालकों को एक क्रिमिनल की भांति न ट्रीट किया जाए और जबरन जेंडर सेंसेटाइज़ेशन क्लास ओर जीपीएस ट्रेकिंग से मुक्त किया जाए। यदि आप कोई उचित समाधान नही करते है तो मजबूरन हमे धरना, भूख हड़ताल, आमरण अनशन करना या माननीय अदालत की शरण में जाना होगा।

उम्मीद है कि आप तमाम चालको मायूस नही करेंगे।

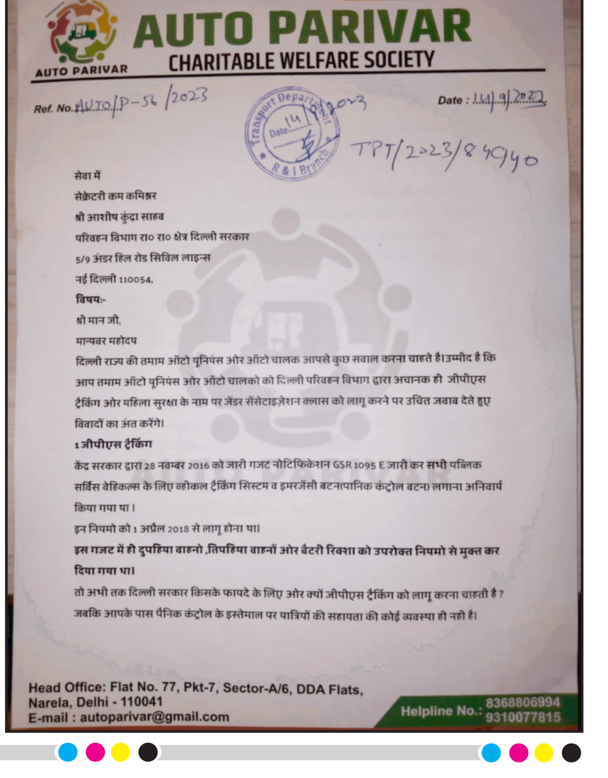

Regd. No.: ROS/North/NL/263/2020

AUTO PARIVAR
CHARITABLE WELFARE SOCIETY

Ref. No. AUTO/P-56 /2023

Date : 14/9/2023

TPT/2023/84940

सेवा में
सेक्रेटरी कम कमिश्नर
श्री आशीष कुंद्रा साहब
परिवहन विभाग रा० रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार
5/9 अंडर हिल रोड सिविल लाइन्स
नई दिल्ली 110054,
विषय:-
श्री मान जी,
मान्यवर महोदय
दिल्ली राज्य की तमाम ऑटो यूनियंस ओर ऑटो चालक आपसे कुछ सवाल करना चाहते है। उम्मीद है कि आप तमाम ऑटो यूनियंस ओर ऑटो चालको को दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा अचानक ही जीपीएस ट्रैकिंग ओर महिला सुरक्षा के नाम पर जेंडर सेंसेटाइज़ेशन क्लास को लागू करने पर उचित जवाब देते हुए विवादों का अंत करेंगे।
1 जीपीएस ट्रैकिंग
केंद्र सरकार द्वारा 28 नवम्बर 2016 को जारी गजट नोटिफिकेशन GSR 1095 E जारी कर सभी पब्लिक सर्विस वेहिकल्स के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम व इमरजेंसी बटन(पानिक कंट्रोल बटन) लगाना अनिवार्य किया गया था।
इन नियमो को 1 अप्रैल 2018 से लागू होना था।
इस गजट में ही दुपहिया वाहनो ,तिपहिया वाहनों ओर बैटरी रिक्शा को उपरोक्त नियमो से मुक्त कर दिया गया था।
तो अभी तक दिल्ली सरकार किसके फायदे के लिए ओर क्यों जीपीएस ट्रैकिंग को लागू करना चाहती है ?
जबकि आपके पास पैनिक कंट्रोल के इस्तेमाल पर यात्रियों की सहायता की कोई व्यवस्था ही नही है।

Head Office: Flat No. 77, Pkt-7, Sector-A/6, DDA Flats,
Narela, Delhi - 110041
E-mail : autoparivar@gmail.com

Helpline No.: 8368806994 9310077815

ये हैं 5 पतिव्रता स्त्रियां, जिनका महाभारत और रामायण में भी मिलता है उल्लेख

हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों के लिए पतिव्रता होना एक श्रेष्ठ गुण माना गया है। प्राचीन काल में ऐसी कई स्त्रियों की कथा मिलती है जिन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही पतिव्रता स्त्रियों का बारे में जिनका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है।

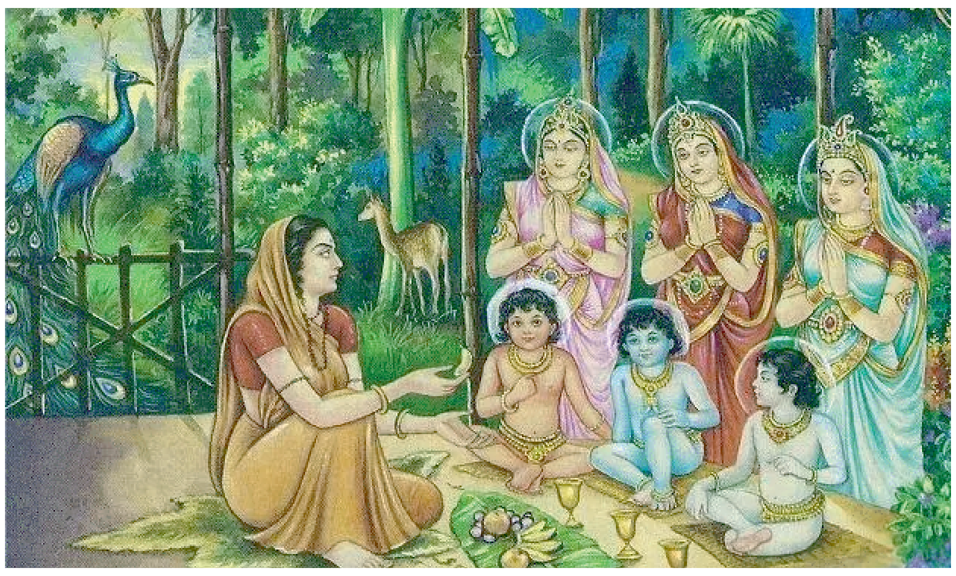

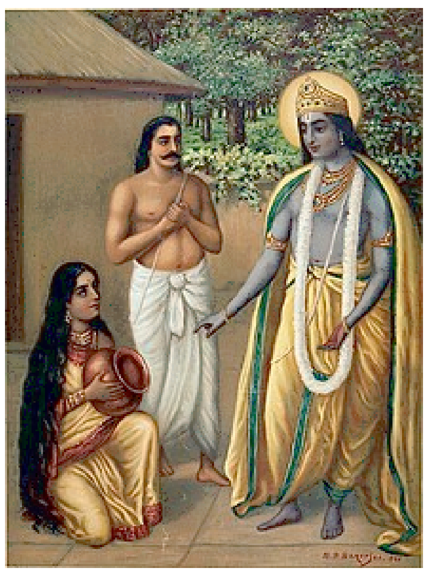

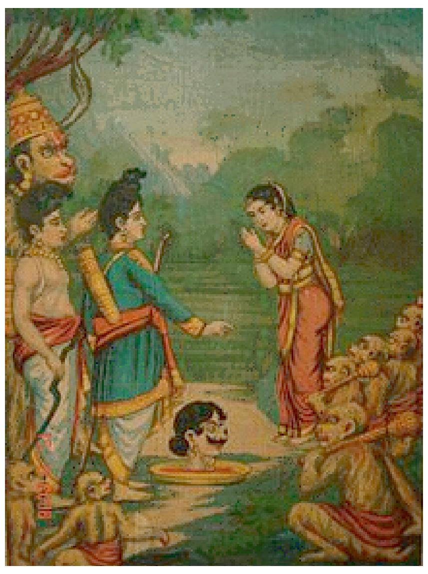

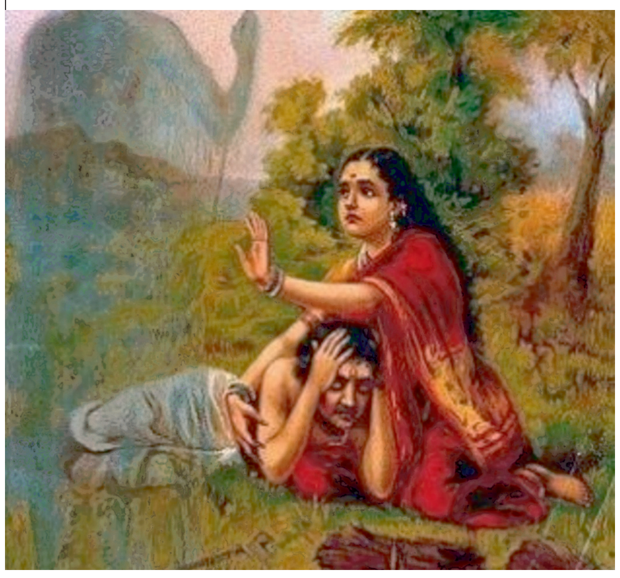

महाभारत और रामायण में ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जो व्यक्ति को आश्चर्य में डाल सकती हैं। साथ ही इनमें कुछ ऐसी विवाहित स्त्रियों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने के कारण श्रेष्ठ माना गया है।

1. अनुसूया

पतिव्रता देवियों में अनुसूया को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थीं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती कि एक बार देवी सरस्वती, माता लक्ष्मी और मां दुर्गा में यह विवाद छिड़ा कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है? अंत में तय हुआ कि अत्रि मुनि की पत्नी अनुसूया ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं।

इस बात की परीक्षा लेने के लिए एक बार त्रिदेव-ब्रह्मा, विष्णु और महेश अनुसूया के आश्रम में ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए पहुचे। उन्होंने अनुसूया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसूया ने अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसूया ने देवी सीता को भी पतिव्रता का उपदेश दिया था।

2. द्रौपदी

द्रौपदी का विवाह पांच पांडवों के साथ हुआ था। लेकिन द्रौपदी को सती के साथ ही पांच कुंवारी कन्याओं में भी शामिल किया जाता है। एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था। जब पांडव द्रौपदी को साथ लेकर माता कुंती के पास पहुंचे और द्वार से ही अर्जुन ने पुकारकर कहा कि आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। इस पर कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि तुम जो भी लाए हो आपस में उसे बांट लो।

बाद में यह पता चलने पर कि भिक्षा वधू के रूप में हैं, कुंती को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए पांडवों ने ठीक वैसा ही किया। एक कीचक और जरासंध ने द्रौपदी के मान को भंग करने का प्रयास भी किया लेकिन द्रौपदी ने विषम परिस्थिति में संयम का पालन किया और अपने सतीत्व की रक्षा की। इसलिए द्रौपदी भी पतिव्रता नारियों में से एक कहलाती हैं।

3. सुलक्षणा

सुलक्षणा रावण के पुत्र मेघनाथ (इंद्रजीत) की पत्नी थीं। जिसे सुलोचना भी कहा जाता था। इन्हें भी पांच सतियों में शामिल किया गया है। रामायण की कथा के अनुसार रावण ने मेघनाथ को रणभूमि में युद्ध के लिए उतारा था। राम की शक्ति से मेघनाथ की पत्नी सुलक्षणा परिचित थी, इसलिए उसने मेघनाथ को रणभूमि में जाने से रोका था। लेकिन मेघनाद नहीं माना और युद्ध में मेघनाथ को मृत्यु प्राप्त हुई। इसके बाद सुलक्षणा भी सती हो गईं।

4. सावित्री

जब पतिव्रता नारियों की बात होती है तो सावित्री का नाम सबसे पहले याद आता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा मिलती है। महाभारत अनुसार सावित्री राजर्षि अश्वपति की पुत्री थी। उनके पति का नाम सत्यवान था, जो वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु के बाद, सावित्री ने अपनी तपस्या के बल पर सत्यवान को पुनर्जीवित कर लिया था। जिस कारण सावित्री को पतिव्रता कहा जाता है। इनके नाम से वट सावित्री नामक व्रत प्रचलित है, जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं।

5. मंदोदरी

लंकापति रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। उन्हें में पतिव्रता स्त्रियों में गिना जाता है। रावण की धर्मपत्नी होने के बाद भी मंदोदरी बहुत पवित्र और महान स्त्री थी। मंदोदरी ने हमेशा रावण के गलत कार्यों के लिए रोका, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं मानी। इसके बाद भी मंदोदरी ने पतिव्रता के नियमों का पूरा पालन किया। मंदोदरी को विद्वान स्त्री भी माना जाता है।

जानिए कौन है 51 हजार सांप पकड़ने वाली ये महिला, नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित

सांप भी हो सकते हैं हमारे मित्र। यह कहती हैं 'सर्पमित्र' के नाम से लोकप्रिय महाराष्ट्र की वनिता जगदेव बोराडे। स्वावलंबन की अलग और अनूठी राह पर चलने वाली वनिता को सर्प संरक्षण के लिए देश-विदेश में सराहना मिलती रहती है।

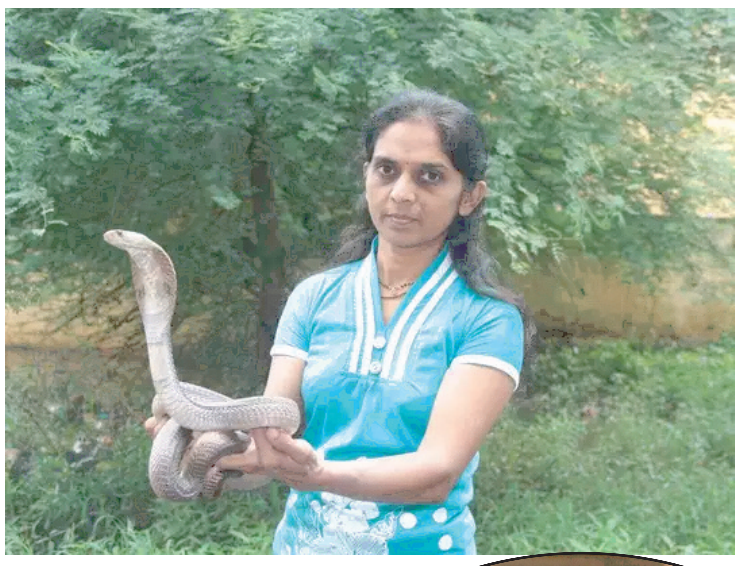

केवल दसवीं तक पढ़ाई की है, पर वनिता इंसान ही नहीं, जीव-जंतुओं की भी भाव भंगिमा पढ़ने की विशेषज्ञ हैं। अपने खेतों में काम कर रहे आदिवासी बच्चों के संग खेलते-कूदते हुए बड़ी हुईं और उनके रंग में रंगती चली गईं, जैसे पेड़ों पर चढ़ना, कई फीट गहरे कुंए में उतर जाना, नदियों में दूर तक तैरकर निकल जाना, मछली पकड़ना व जंगली जंतुओं के बीच रहना उनकी दिनचर्या बन गई। वनिता के पिता और परिवारवालों को इसकी खबर नहीं थी कि आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए वह एक दिन ऐसी बहादुर स्त्री बन जाएंगी, उलटा वे सांपों के साथ खेलने के कारण उन्हें कसकर डांट लगा देते थे। वनिता कहती हैं, सांपों की जान बचाने के लिए मैं घरवालों की डांट और मार आसानी से सह लेती थी। धीरे-धीरे वनिता को लोग 'सर्पमित्र' कहने लगे। वह सांपों को देखकर ही पहचान लेती हैं कि वह किस प्रजाति का है।

आम ग्रामीण लड़कियों की तरह वनिता की शादी भी कम उम्र में हो गई, पर शादी के बाद भी उनकी सर्पों से मित्रता न केवल जारी रही, बल्कि समय के साथ यह और गाढ़ी होती गई। दरअसल, अब उन्हें पति का पूरा साथ भी मिल रहा था। हालांकि शुरुआती दिनों में पति भी वनिता के कारनामों को देखकर हैरान थे। हैरानी से अधिक डर था कि कहीं जहरीले सांपों से खेलने का यह जुनून उनकी जिंदगी न छीन ले। आखिरकार पति का यह डर वनिता के लगन और जिद के आगे हार गया। इसके बाद उन्होंने वनिता का साथ देने का फैसला कर लिया।

वनिता की शादी हुए 22 साल हो गए हैं, उनका परिवार न केवल उस इलाके (बुलढाना, महाराष्ट्र) में बल्कि देश-दुनिया में प्रसिद्ध है। वनिता को लोग इंटरनेट मीडिया के जरिए खूब जानते हैं। वनिता अपने पति डी भास्कर के लिए 'मैडम जी' हैं। दरअसल, वह वनिता को घर पर मैडम जी ही कहते हैं। कारण पूछने पर खिलखिलाते हुए कहते हैं, आज लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, बल्कि उनके नाम से जानते हैं। लोग मिस्टर भास्कर नहीं मिस्टर बोराडे कहते हैं। इसलिए वह मेरी मैडम जी हैं।

वनिता यह सुनकर कृतज्ञता से भर उठती हैं। वह कहती हैं, मेरा तो पशु-पक्षियों के बीच बचपन बीता है। बस जिद थी कि इन बेजुबानों को निर्दोष नहीं मरने देना है। इससे आगे की कहानी पति के साथ मिलकर शुरू होती है। वनिता के चार बच्चे हैं। पति भास्कर के अनुसार, वनिता कभी घर नहीं बैठतीं। उन दिनों में भी जब वह गर्भवती थीं, अपने मिशन पर तैनात रहती थीं। तैनाती ऐसी जैसे कि वह एक मिलिट्री वुमन हों। हरदम तैयार। गांव में कहीं सांप निकलने की खबर फैलती है तो लोग वन्य विभाग से पहले वनिता को बुलावा भेजते हैं। वह भी संदेश मिलते ही तुरंत निकल पड़ती हैं।

वनिता कहती हैं, मेरे लिए जितना घर का काम और बच्चों की परवरिश जरूरी है, उतना ही जरूरी सांपों का संरक्षण है। वनिता को अन्य जंगली जीव-जंतुओं से भी डर नहीं लगता। घर पर कभी भी बच्चे किसी जानवर को उठा ले आते हैं। कोई अतिथि आ जाए तो वह इतना भयभीत हो जाता है कि कई वर्ष तक नहीं भूल पाता। हालांकि वनिता इस बात का पूरा खयाल रखती हैं कि अतिथियों को कोई नुकसान न पहुंचे। वह बड़े से बड़े मधुमक्खी के छत्ते को यूं गिरा देती हैं, जैसे कि उनके हाथों में जादू की कोई छड़ी हो।

सांपों को बचाने का यह जुनून कब सवार हो गया, कभी डर नहीं लगा? इस सवाल के जवाब में वनिता कहती हैं, एक छोटी सी कहानी है। मैंने एक बार मछली पकड़ने वाले जाल में देखा कि उसमें एक सांप भी है। वह पानी वाला सांप था, लेकिन उस वक्त नहीं मालूम था कि यह जहरीला नहीं है। मैंने उसे हाथों में लिया तो डर लगा, लेकिन जब उसने नहीं काटा तो मेरा डर खत्म हो गया।
वनिता के मुताबिक, उस दिन के बाद से ऐसी घटनाएं कई बार हुईं। नतीजतन हर बार सांपों के और करीब होती गई। अब सांपों से डर नहीं लगता है, बल्कि उनके प्रति लोगों के डर को दूर करना चाहती हूं। इस बाबत अभियान भी चला रही हूं।

वनिता कहती हैं, सांपों को लेकर समाज में कई नकारात्मक बातें व्याप्त हैं साथ ही मिथक भी हैं। ये सब उनके संरक्षण में बड़ी बाधा हैं। सांप हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। वे किसानों की फसल तबाह होने से बचाते हैं। वे यूं ही कभी नहीं काटते, लोग जानकारी के अभाव में डरते हैं। वनिता के पति कीर्तन-प्रवचन करते हैं। वह आध्यात्मिक हैं, लेकिन यह सामान्य से अलग है। वह सर्प कीर्तन करते हैं जिसमें कि धार्मिक ग्रंथों में जीव-जंतुओं की रक्षा का संदेश सुनाया जाता है। वह जागरूकता संबंधी अन्य कार्यक्रम भी करते हैं। इसमें संत तुकाराम की उक्तियों की मदद ली जाती है, उन्होंने कहा था कि हमारी संस्कृति कैसे प्रकृति के साथ सहचर रहते हुए आगे बढ़ी है। हरेक जीव में ईश्वर का वास है और हर कोई ईश्वर की अप्रतिम कलाकृति है। यदि हम किसी जीव को मारते हैं तो सृष्टि चक्र के लिए वह एक बड़ा अपराध होता है। इस खास तरह के कीर्तन में सांपों और अन्य जीव-जंतुओं से जुड़ी तमाम तरह की भ्रांतियां दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए पति-पत्नी खूब अध्ययन भी करते हैं।

वनिता का 'सोयरे वन्यचरे' नामक एक बहुद्देश्यीय फाउंडेशन भी है। यह सांपों के संरक्षण और उनके संवर्धन के कार्यों में जुटा रहता है। उनके कार्यों की धमक दूर तक है। बाबा आम्टे से उन्हें सराहना मिली है। संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना के लिए जुटी संस्था डब्ल्यूसीपीए से भी उन्हें प्रशंसा मिली है। डब्ल्यूसीपीए ने सर्प संरक्षण के कार्य के लिए वनिता को सम्मानित किया है साथ ही इस संस्था ने उन्हें आजीवन सदस्यता दी है।

वनिता के नाम 51 हजार सांप पकड़ने का रिकार्ड भी दर्ज है। वनिता के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने पांच रुपये का डाक टिकट भी जारी किया है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के कार्यकाल में हुआ था। इस वर्ष राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार पाकर वह गदगद हैं। अब वह एक ऐसा एंटीस्नेक डाट का निर्माण करना चाहती हैं, जिसकी मदद से सर्पदंश से होने वाले खतरे से बचाव हो सके।

एक दिन में कितने अखरोट खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद

ड्राई फ्रूट्स और सीड्स सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो अखरोट का सेवन बहुत से लोग करते हैं। माएं भी अक्सर अपने बच्चों को अखरोट खिलाती हैं। इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। प्रोटीन, फैट, कैल्शियम और आयरन इनमें काफी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो कॉर्डियोवैस्कुलर रोगों को दूर करने में मदद करता है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि एक दिन में कितने अखरोट खाने सेहत के लिए फायदेमंद रहेंगे। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि दिन में आप कितने अखरोट का सेवन कर सकते हैं...

एक दिन में कितने अखरोट खाने चाहिए?

इसका सेवन करने से स्वास्थ्य को अनगिनत फायदे होते हैं परंतु एक दिन में आपको कितने अखरोट खाने चाहिए यह बात आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसके अलावा यदि आप कोलेस्ट्रॉल का स्तर शरीर में से कम करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स के अनुसार, रोज 30-60 ग्राम अखरोट खाने फायदेमंद रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होने से हार्ट भी स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा यदि आपको किसी तरह की कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो आप अखरोट का सेवन रोज कर सकते हैं।

वजन होगा कम

इसका सेवन करने से भूख कंट्रोल होती है जिससे आप ओवरइटिंग करने से बचेंगे। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

डायबिटीज का खतरा कम

इसमें मौजूद पोषक तत्व इंसुलिन को रोकने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसका सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है।

पेट के लिए फायदेमंद

रिपोर्ट्स के अनुसार, अखरोट पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया पेट की स्वास्थ्य को सही रखने में मदद करते हैं।

दिमाग के लिए फायदेमंद

उम्र बढ़ने का असर याददाश्त पर पड़ता है जिसके कारण यह कमजोर होने लगती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ-साथ अल्जाइमर जैसे रोग का खतरा भी बढ़ता है। ऐसे में आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने से दिमाग से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है। इसके अलावा अखरोट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने और नवर्स सिस्टम की सूजन कम करने में मदद करता है।

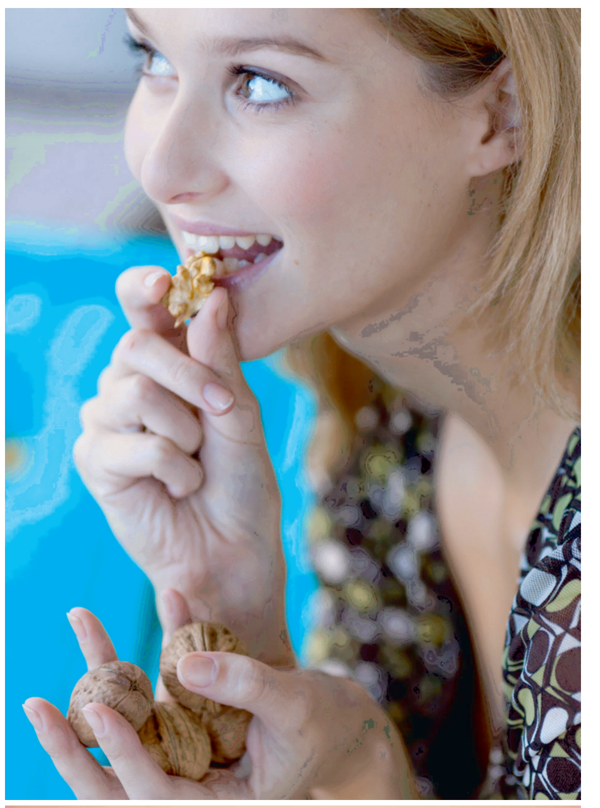

डूसू चुनाव में एबीवीपी का वर्चस्व, 10 साल में सात बार अध्यक्ष पद पर किया कब्जा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव 22 सितंबर को होने हैं। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी छात्र संगठन कालेजों में प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। हर संगठन अपनी जीत का दावा कर रहा है लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी संगठनों से आगे नजर आ रही है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) पूरी ताकत से लड़ रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव 22 सितंबर को होने हैं। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी छात्र संगठन कालेजों में प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। हर संगठन अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी संगठनों से आगे नजर आ रही है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) पूरी ताकत से लड़ रही है। डूसू चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव चुने जाते हैं। 2010 में अभाविप ने तीन पद अपने नाम किए थे। एनएसयूआइ के खाते में संयुक्त सचिव का पद आया था। 2011 में एनएसयूआइ अध्यक्ष पद जीतने में कामयाब रही थी। शेष तीन पद अभाविप ने जीते थे। 2012 में सभी पदों पर एनएसयूआइ ने जीत हासिल की थी।

2013 में एनएसयूआइ को सचिव पद हासिल हुआ था। अध्यक्ष समेत तीन पदों पर अभाविप ने कब्जा जमाया था। 2014 में सभी पद अभाविप ने जीते थे। 2015 में भी अभाविप ने क्लीन स्वीप किया था। 2016 में वापसी करते हुए एनएसयूआइ ने संयुक्त सचिव का पद जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 2017 में मुकाबला कांटे का रहा था।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद एनएसयूआइ ने और सचिव व संयुक्त सचिव के पद अभाविप ने जीते थे। 2018 में अभाविप ने वापसी करते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पदों पर कब्जा जमाया था, जबकि एनएसयूआइ अपना सचिव बनाने में कामयाब रही थी। 2019 में भी चुनाव परिणाम 2018 की तरह आए थे।

पिछले 10 वर्षों में जीते अध्यक्ष पद के उम्मीदवार

साल	नाम	संगठन
2010	जितेंद्र चौधरी	ABVP
2011	अजय चिकारा	NSUI
2012	अरुण हुड्डा	NSUI
2013	अमन अवाना	ABVP
2014	मोहित नागर	ABVP
2015	सतेंद्र अवाना	ABVP
2016	अमित तंवर	ABVP
2017	राकी तुसीद	NSUI
2018	अंकिव बैसोया	ABVP
2019	अक्षित दहिया	ABVP

कोविड के चलते 4 साल नहीं हुआ चुनाव

इसके बाद कोविड महामारी के चलते चुनाव नहीं हो सके। अब चार साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। अभाविप के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशुतोष सिंह ने कहा, अभाविप चुनाव में पूरी तैयारी से उतरी है। सभी सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। अगले सात दिन प्रचार अभियान को और तेज किया जाएगा।

एनएसयूआइ के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली के प्रभारी नीतीश गौड़ ने कहा, संगठन की पूरी तैयारी है। हर कालेज के छात्र से संवाद स्थापित किया गया है। हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और सभी सीटें जीतेंगे। स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया और आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव में कितना असर डालेंगे, यह देखना बाकी है।

आप ने छात्रसंघ चुनाव से बनाई दूरी

आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन छात्र युवा संघर्ष समिति ने चुनाव से दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि पंजाब विश्वविद्यालय में एनएसयूआइ की जीत के बाद आप के छात्र संगठन ने डूसू चुनाव से दूरी बनाई है। प्रदेश सचिव कमल तिवारी ने कहा, पार्टी की ओर से उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए बोला गया था। इसलिए वे भाग नहीं ले रहे हैं। बता दें कि डूसू चुनाव में 52 कालेज के छात्र मतदान करते हैं। एक लाख से अधिक मतदाता चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ईवीएम पर मतदान किया जाता है।

भक्तजनों अब न करना ये गलती: दिल्ली में मूर्ति विसर्जन पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना; जारी हुई ये गाइडलाइन

यमुना में मूर्ति विसर्जित करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडबल्यूए) और आम लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

नई दिल्ली। गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा के दौरान यमुना नदी में मूर्ति विसर्जित करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (डीपीसीसी) ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीपीसीसी ने साफ किया कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) के 2019 और 2021 में जारी आदेश के अनुसार, गंगा और सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन करने पर 50 हजार रुपये का पर्यावरण क्षति शुल्क लगाया जाएगा। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडबल्यूए) और आम लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मूर्ति विसर्जन टब या बाल्टी में ही करें। इसके साथ ही पूजन सामग्री जैसे फूल, सजावटी सामान विसर्जन से पहले मूर्ति से हटा लें। पूजा में पीओपी से बनी मूर्ति का विसर्जन झीलों, तालाबों और नदियों में न करें। इसके साथ ही मूर्तिकारों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि मूर्ति बनाने के लिए प्राकृतिक मिट्टी और सजाने के लिए प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करें। यही नहीं पीओपी की मूर्तियां तलाबों, नदियों और जोहड़ों, झीलों में विसर्जित नहीं की जा सकती। डीपीसीसी ने विभागों के लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी किए हैं। इसमें दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली पुलिस वाहनों की जांच करे की कोई भी मूर्ति का विसर्जन करने यमुना तक न आए। वहीं, सिविक एजेंसियां मूर्ति विसर्जन के लिए अस्थायी तालाबों का इंतजाम करें।

जैसा बोओगे, वैसा काटोगे

अपनी मृत्यु ! अपनों की मृत्यु ! मनुष्य को सदैव डरावनी लगती है। बाकी की तो मौत का उत्सव मनाता है मनुष्य !

आखिर क्यों ??

मौत के स्वाद का चटखारे लेता है मनुष्य ! मौत तो हमारा स्वाद है। मौत किसी की, और स्वाद हमारा, यह कैसा नियम है मनुष्य का..!

स्वाद के कारण ही मौत कारोबार बन गई है। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम है 'पालन' और मकसद है ₹हत्या₹ करना। स्लाटर हाउस तक खोल दिये गये हैं। गली-गली में खुले नॉनवेज रेस्टॉरेंट ! मौत का कारोबार नहीं तो और क्या हैं ?

यह सब इसलिए है क्योंकि यह मौत हमारी नही है, किसी और की है। जो हमारी तरह बोल नही सकते, अपनी अभिव्यक्त नही कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं। उनकी इस कमजोरी को हमने अपना बल मान लिया है ! और साथ ही साथ हमने यह मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होतीं है ? या उनकी आहें नहीं निकलतीं हैं ? या उनकी बददुवाएं नहीं होती हैं।

खाने की टेबिल पर हड्डियां नोचते हुए, एक पिता अपने बच्चे को सीख देता है, कि बेटा कभी किसी का दिल नही दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारे कारण, आँसू नहीं आना चाहिए । अपने बच्चों में झूठे संस्कार डालते समय पिता को, अपने हाथ मे वो हड्डियाँ नहीं दिखती, जो इससे पहले एक जीवित शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी, उसकी भी अपनी एक मां थी, और वह भी किसी की संतान थी। जिसे काटा गया होगा ? क्या वह कराहा नहीं होगा ? या तड़पा होगा। उसकी भी आहें अवश्य निकली होंगी ? और उसने बददुवाएं भी अवश्य दी होगी ?

आपने कैसे यह मान लिया कि जब-जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तब ईश्वर सिर्फ मनुष्यों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे ? क्या ये मूक जानवर उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं हैं ? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है ?

धर्म की आड़ में उस परमपिता के नाम पर आप लोगों ने अपने स्वाद के लिए कभी 'ईद' पर बकरे को काटते हो, तो कभी 'माँ दुर्गा' या 'बाबा भैरव' के सामने बकरे की बली चढ़ाते हो। तो कहीं आप, अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते है ।

क्या अपने कभी सोचा ! कि ईश्वर का स्वाद क्या होता है ? उनका भोजन क्या है ? आखिर आप किसे ठग रहे हो ! भगवान को, अल्लाह को, जीसस को या स्वयं को ?

मंगलवार को मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, आज शनिवार है इसलिए नॉनवेज नहीं खाऊंगा, अभी नवरात्रि चल रही हैं, इसलिए नॉनवेज नहीं खाऊंगा। इसका मतलब ! आपके मन में भी कहीं न कहीं अपराध बोध अवश्य है। परंतु वह आपकी जिव्हा के स्वाद के आगे गौण हो गया है।

ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, और मनुष्य योनि में जन्म दिया। सिर्फ इसलिए कि आप तमाम योनियों में भटकने के बाद, जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता ढूँढ सके। परन्तु आपने इस मनुष्य योनि को पाते ही स्वयं को ईश्वर समझ लिया।

आप ही तो कहते हो, कि हम जो प्रकृति को देंगें, वही प्रकृति हमें लौटायेगी। यदि आप प्रकृति को मौतें दे रहे हैं, तो प्रकृति भी हमें मौत ही लौटायेगी। तब अपनों की मौत पर कष्ट क्यों ? यह विलाप कैसा !

आसामयिक मौत, असाध्य रोग और अन्य दैवीय आपदाएँ ! क्या यह, इस बात का संकेत नही है कि ईश्वर हमसे नाराज है।

ईश्वर ने अपनी ही, बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुका हैं, और आगे भी ऐसा ही कर रहा है।

शाकाहार, तप, त्याग और तपस्या ही मानव का धर्म है।

जियो और जीने दो₹ ही मनुष्य योनि का सतत सत्य सिद्धान्त है, और इसी राह पर चलने वाला मनुष्य सदैव दीर्घायु, सुखी और यशश्वी रहता है। प्रकृति के साथ रहो।

आरक्षण से किसी मानस को कोई आपत्ति नहीं है

आपत्ति है तो यह है कि जिसको आरक्षण दिया जा रहा है वो सामान्य आदमी बन ही नहीं पा रहा है !

समय सीमा तय हो जो व्यक्ति विशेष जाति में पैदा हुआ हैं वह सामान्य नागरिक कब बन जायेगा ?

किसी व्यक्ति को आरक्षण दिया गया और वो किसी सरकारी नौकरी में आ गया ! अब उसका वेतन 25000 से 50000 व इससे भी अधिक है , पर जब उसकी संतान हुई तो वह भी पिछडी ही पैदा हुई जबकि उसका जन्म हुआ प्राईवेट अस्पताल में पालन पोषण हुआ राजसी माहोल में ₹फिर भी वह गरीब पिछड़ा और सवर्णों के अत्याचार का मारा हुआ ?

उसका पिता लाखों रूपए सालाना कमा रहा है उच्च पद पर आसीन है ! सारी सरकारी सुविधाएं ले रहा है ! वो खुद जिले के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है , और सरकार उसे पिछड़ा मान रही है सदियों से सवर्णों के अत्याचार का शिकार मान रही है !

आपको आरक्षण देना है , बिलकुल दो पर उसे नौकरी देने के बाद तो सामान्य बना दो ! ये गरीबी ओर पिछड़ा दलित आदमी होने का तमगा तो हटा दो !

यह आरक्षण कब तक मिलता रहेगा इसकी कोई समय सीमा तय कर दो या बस जाति विशेष में पैदा हो गया तो आरक्षण का हकदार हो गया , और वह कभी सामान्य नागरिक नही होगा !

दादा जी जुल्म के मारे !

बाप जुल्म का मारा !

अब ... पोता भी जुल्म का मारा !

आगे जो पैदा होगा वह भी जुल्म का मारा ही पैदा होगा ! पहले से ही तय कर रहे हो ?

वाह रे मेरे देश का राजनीतिक दुर्भाग्य ! वाह रे महान देश !

जिस आरक्षण से उच्च पदस्थ अधिकारी, मन्त्री, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर भी पिछड़े ही रह जायें, गरीब ही बने रहें ऐसे अभियान को तुरंत बंद कर देना चाहिए !

क्या जिस कार्य से कोई आगे न बढ़ रहा हो उसे जारी रखना मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है ?

हम में से कोई भी आरक्षण के खिलाफ नहीं, पर आरक्षण का आधार जातिगत ना होकर आर्थिक होना चाहिए !

सबका साथ सबका विकास

अन्त्योदय योजना लाओ ₹अंत को सबल बनाओ !

और तत्काल प्रभाव से प्रमोशन में आरक्षण बंद करे, नैतिकता भी यही कहती है और संविधान की मर्यादा भी !

क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर में प्रसाद बँट रहा हो और एक व्यक्ति को चार बार मिल जाये और अन्य व्यक्ति लाइन में रहकर अपनी बारी का इंतजार ही करता रहेगा ?

आरक्षण देना है तो उन गरीबों लाचारों को चुन चुन के दो जो बेचारे दो वक्त की रोटी को मोहताज हैं... चाहे वे अनपढ़ ही क्यों न हों ! चौकीदार, सफाई कर्मचारी , सेक्युरिटी गार्ड कैसी भी नौकरी दो ! हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही होगी ! ऐसे लोंगो को मुख्य धारा में लाना सरकार का सामाजिक व नैतिक उत्तरदायित्व भी है ! परन्तु भरे पेट वालों को बार बार 56 व्यंजन परोसने की यह नीति बंद होनी ही चाहिए !

जिसे एक बार आरक्षण मिल गया , उसकी अगली पीढ़ियों को सामान्य मानना चाहिये और आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिये !

अगर सहमत हो तो जन-जन तक पहुचायें,

दिल्ली के पहले नेचुरोपैथी 'बीवाईएम वेलनेस सेंटर' का हुआ शुभारंभ

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मालवीय नगर में बी वाई एम वैलनेस सेंटर पिछले दिनों खुला, जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन रहा । चंद्रयान को चंद्रमा के पास हमारे वैज्ञानिकों ने भेजा और आज के दिन मालवीय नगर में बी वाई एम वैलनेस सेंटर का उद्घाटन माननीय वाई पी सिंह जी के द्वारा हुआ ।वाई पी सिंह जी ग्रीनवे नर्सरी के मालिक हैं और इंडियन नर्सरीमेंन के प्रेसिडेंट भी हैं । बी वाई एम वैलनेस सेंटर पर प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा शरीर में हो रहे बीमारियों का इलाज किया जाता है । यहां पर मिट्टी चिकित्सा , एक्यूप्रेशर , बॉडी मसाज , स्टीम बाथ , षट्कर्म (जल नेती, सूत्र नेती, दण्ड, धौती, कुंजन क्रिया तथा एनीमा) और योग के द्वारा अनुभवी चिकित्सक के देख रेख में रोगों का उपचार किया जाता है । बी वाई एम वैलनेस सेंटर डॉ प्रदीप पांडेय जी के देखरेख में चलाया जाता है तथा भारतीय योग महासंघ के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर सुनीता जी, डाक्टर गोवर्धनी जी, डाक्टर अतुला जी और मसाज़ के लिए स्पेशलिस्ट श्रीमति रीना जी, श्रीमान दिनेश जी और योग शिक्षक श्रीमान रोहित जी, विक्रम जी, संदीप जी, पुनीत जी और योग गुरु प्रदीप पांडेय जी के द्वारा योग कक्षा का संचालन किया जाता हैं किया जाता है । अंत में भारतीय योग महासंघ के अध्यक्ष योग गुरु प्रदीप पांडे जी ने श्रीमान वाई पी सिंह जी का धन्यवाद मालाओं के द्वारा और हमारे उपस्थित सभी भारतीय योग महासंघ के योग शिक्षक , प्राकृतिक शिक्षक , एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट , पावर योगा एक्सपर्ट , सब ने उनको धन्यवाद दिया ।अंत में श्रीमान वाई पी सिंह जी ने सभी भारतीयों योग महासंघ के पैनल पर कार्य कर रहे सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी और यह उम्मीद किया कि मालवीय नगर में इस प्रकृति चिकित्सा को अपने रोगों के लिए , अपने को स्वस्थ रखने में प्रत्येक व्यक्ति लाभ उठाएगा । वाई पी सिंह जी का कहना था की पांडे जी बड़े समय से योग चिकित्सा के फील्ड में है और अभी तक इन्होंने अनेक योग और प्राकृतिक प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देकर , अनेकों स्थान पर अपने टीम को भेजा गया है और इनका अंत में धन्यवाद करता हूं और कभी भी मेरी आवश्यकता हो इस प्रकृति चिकित्सा और भारतीय संस्कृति के लिए मैं सदैव खड़ा रहूंगा । इस भारतीय योग महासंघ का अतुल्य सहयोग इस फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद करता हूं ।

सरकार द्वारा प्रदुषण नियंत्रण के लिए की जाने वाली सख्ती हमारे और हमारे अपनो के हित के लिए...

प्रदूषण मानव का ही नहीं जीव-जन्तु, प्राणी, वनस्पति के लिए भी विनाशक

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हम सब का प्रथम कर्तव्य है की प्रदुषण मुक्त साम्राज्य स्थापित करने में योगदान प्रदान करे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमे हर मौके पर पेड़ पौधे लगाने और उनका ध्यान रखना आवश्यक है,

हमे कूड़ा कचरा सही स्थान पर डालने का संकल्प लेना आवश्यक है,

हमे अपने वाहनों की सर्विस समय पर करवाना और प्रदुषण प्रमाण पत्र समय पर लेना आवश्यक है,

हमे वाहन अपनी सही लाइन में चलाने की आदत डालना आवश्यक है जिससे सड़को पर कही भी पूर्ण जाम लगने की स्थिति पैदा ना हो,

सरकार द्वारा प्रदुषण नियंत्रण के लिए की जाने वाली सख्ती हमारे और हमारे अपनो के हित के लिए है इस लिए उसका पालन करना अनिवार्य है पर सरकार द्वारा प्रदुषण नियंत्रण के नाम पर जनता पर लगाया जाने वाला भारी जुर्माना गलत है क्योंकि प्रदुषण के बढने के लिए जनता से भी अधिक ज्यादा जिम्मेदार स्वयं सरकार या सरकारी पदो पर आसिन बड़े अधिकारी हैं। सड़को पर कूड़े कचरे के ढेर, सड़को पर अनाधिकृत कब्जे, टूटी फूटी सड़के, सड़को पर वाहनों के चलने और रुकने के लिए लगाई गई लाल-पीली-हरी बत्ती का खराब रहना या जरुरत अनुसार समय पाबंद ना बनाना, सरकारी कार्यों के लिए सड़को को तोड़ना और फिर टूटा ही छोड़ देना, सड़को पर अनाधिकृत वाहन पार्किंग को बढ़ावा देना इत्यादि सभी वायु गुणवत्ता खराब करवाने में सबसे अधिक गलतियां सरकार और उनके अधीनस्थ कार्यरत आला अधिकारियो की है पर वह सभी तो ताकत और पद की गरिमा से भरपूर होने के कारण सभी गलतियों के लिए जिम्मेदार जनता को बता कर और जनता पर ही उसका दंड लगा कर राजस्व में इज़ाफ़ा और अपने दामन को पाक साफ दिखा देते हैं और न्यायिक प्रणाली में कार्यरत भी सब कुछ जानते हुए भी उनका साथ देते हुए जनता को दोषी करार घोषित कर जुर्माना और सजा सुना रहे हैं।

प्रदूषण की मार, भारी भरकम जुर्माने और अपने पर लगने वाले इल्जामों से बचने के लिए सरकारी आदेशों के इन्तजार की जगह स्वयं को उस कार्य के लिए समर्पित कर दें।

नाली, नालों, नहरो और नदियों में कचरा ना फैंके और ना किसी और को अपने सामने फैंकने दे, व्यवसायिक गतिविधियों में लगे व्यवसाई अपनी फैक्टरी, कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को नाली, नालों, नहरों और नदियों में जाने से रोके और उस गंदे प्रदूषित और केमिकल से भरे जल को अलग बहाए,

इन छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान देने से हम वायु और जल प्रदुषण की मार से काफी हद तक बच सकते है और सरकारी खजाने को बर्बाद होने से भी बचा सकते है उदाहरण के लिए दिल्ली की यमुना नदी को साफ करने के नाम पर खर्च हो चुका अरबों रूपया पर यमुना नदी आज भी नहीं हुई प्रदुषण मुक्त अपने, समाज और देश हित में प्रदुषण नियंत्रण में सहायक बने जिससे कल आने वालो को प्रदुषण मुक्त राज्य मिल सके।

दिल्ली कर्मचारी परिसंघ द्वारा कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिये गेट मीटिंग का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज, नई दिल्ली। आदरणीय साथियो जैसा कि आपको ज्ञात है कि बीते महीने 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन सिविल लाइन जोन वार्ड नं 20 में बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ जहां हमारे दो कर्मचारियों का रोड़ पर कार्य करते समय कार एक्सीडेंट हो गया था। बदकिस्मती से हमारे एक कर्मचारी इंदर पुत्र माईराम मृत्यु को प्राप्त हो गए और दूसरा कर्मचारी जयभगवान पुत्र रामफल गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। जिसके चलते दोनों कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिये 13 सितंबर को 'दिल्ली कर्मचारी परिसंघ' के बैनर तले, परिसंघ के अध्यक्ष संतलाल चावरिया जी के नेतृत्व में सिविल लाइन जोन पर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय श्रमिक संघ के तमाम कर्मठ साथियों का, एवं परिसंघ के सभी सहयोगी सम्मानित साथियों का सिविल लाइन जोन पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद ! ग्रीन पार्क जोन से श्री राजेश रेड्डी जी, श्री सुरेश कागड़ा जी, श्री राजू दुग्गल जी, श्री सोराज हंडाला जी, मौजूद रहे। यह जानकारी निरंजन बिड़ला अध्यक्ष ग्रीन पार्क जोन अखिल भारतीय श्रमिक संघ द्वारा दी गई।

दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत

दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह-सुबह घने बादलों से अंधेरा छा गया। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली/एनसीआर। एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर सुबह 7.29 बजे एक मौसम बुलेटिन में आईएमडी ने पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश से आने वाले बादलों के कारण दिल्ली-एनसीआर में 50-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम बारिश के साथ कभी-कभार तीव्र बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग का ये अनुमान

तेज हवाओं के साथ अचानक हुई बारिश से शहर को पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 9.30 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर धीरे-धीरे कम हो जाएगा।

तेज़ हवाओं के साथ अचानक भारी बारिश

शुक्रवार सुबह दिल्ली और पड़ोसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ अचानक भारी बारिश हुई। वसंत विहार, मुनिरका और आरके पुरम सहित दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तड़के हल्की बारिश हुई।

हरियाणा के गुरुग्राम में भी सुबह हवाओं के साथ तेज बारिश हुई।

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अचानक मौसम में बदलाव देखा गया। कई इलाकों में बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम में बदलाव देखा गया। कई इलाकों में बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है।

मौसम विभाग ने जताई ये संभावना

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह लगभग 09:30 बजे तक उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाले बादलों के कारण 50-70 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाए चलने और मध्यम बारिश के साथ कभी-कभी तीव्र बारिश होने की संभावना है। उसके बाद तेज हवाएं और बारिश का दौर धीरे-धीरे कम हो जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बदलाव हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आज बादल बरसेंगे।

ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन बिल्डिंग में पैसेंजर लिफ्ट गिरी, चार मजदूरों की मौत

ग्रेटर नोएडा में एक मूर्ति के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग में बड़ा हादसा है। हादसे में चार मजदूरों की मौत की सूचना है।

ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंच रही है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा सीईओ एनजी रवि और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जिला अस्पताल पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मूर्ति के पास ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में निर्माणाधीन साइट पर मजदूर काम कर रहे थे। अचानक पैसेंजर लिफ्ट गिर गई है। हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना: गाजियाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से चार लोग झुलसे, एक किशोरी की हुई मौत

शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश के बीच बिजली गिरने से इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के मकनपुर में चार लोगों के झुलसने और 15 साल की किशोरी की मौत हो गई।

गाजियाबाद। मकनपुर गांव में शुक्रवार सुबह नौ बजे बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 14 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 17 साल की किशोरी और तीन महिलाएं झुलस गई। सभी को तुरंत संजय नगर के संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर उपचार कर रहे हैं। पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस के मुताबिक, मकनपुर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली 14 साल की अजमेरी, 17 साल की जैसमीन, 37 वर्षीय अजमेरी खातून, 40 वर्षीय शालौ और शबाना (40) और नंदिनी को उपचार के लिए संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाएं इंदिरापुरम के सोसायटी में घरेलू सहायिका का काम करती हैं। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे गांव में हनुमान मंदिर के पास से गुजर रही थी, जहां सड़कों पर पानी जमा था। सभी वहीं रुकी, तभी अचानक से आकाशीय बिजली गिर गई। मंदिर के पुजारी व आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

जोरदार धमाके के साथ फटा सिलेंडर, उड़ी मकान की छत; एक महिला हुई घायल

हापुड़। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला न्यू राजीव विहार में शुक्रवार की सुबह को एक घर में जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। धमाके से घर की छत भी उड़ गई।

हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला न्यू राजीव विहार में शुक्रवार की सुबह को एक घर में जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। धमाके से घर की छत भी उड़ गई। शोर सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कोतवाली पुलिस के साथ आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक महिला घायल हो गई। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद में तैनात सुशांत परिवार के साथ मोहल्ला न्यू राजीव विहार में रहते हैं। बताया गया कि शुक्रवार की सुबह को अचानक घर में रसोई गैस सिलेंडर में रखे सिलेंडर में आग लग गई और जोरदार आवाज के साथ सिलेंडर फट गया। धमाके की आवाज सुनकर लोग सहम गए। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। इस हादसे में एक महिला वंदना घायल हो गई। वंदना को लोगों की मदद से आनन फानन में नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत भी उड़कर मलबा दूर जा गिरा। गनीमत रही के आसपास के घरों को नुकसान नहीं हुआ।

जेल में बंद भाई को सिम कार्ड भिजवाने वाले दो गिरफ्तार

गुरुग्राम। जेल में बंद चचेरे भाई को सिम कार्ड पहुंचाने के मामले में अपराध शाखा सेक्टर-31 की टीम ने दो युवकों को बुधवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को जयपुर से और दूसरे को रेवाड़ी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों की पहचान जयपुर निवासी विशाल व रेवाड़ी निवासी प्रवीण के रूप में हुई है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपी प्रवीण के ताऊ का लड़का नवीन एक मामले में भोंडसी जेल में बंद है। पहले उसने विशाल की आईडी पर एक सिम निकलवाई। इसके बाद उसने वह सिम उसे जेल में पहुंचाई। 30 अगस्त को भोंडसी जेल में जांच के दौरान तीन बंदियों के पास एक मोबाइल, चार्जर और इयरफोन मिले थे। इस पर उप अधीक्षक जेल की शिकायत पर भोंडसी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

वकीलों पर लाठी चार्ज: जारी रहेगी अधिवक्ताओं की हड़ताल, हापुड़ बार एसोसिएशन ने दूसरे जिलों से मांगा समर्थन

एसोसिएशन के अध्यक्ष एनुल हक ने इस संबंध में दूसरे जिलों की बार एसोसिएशन अध्यक्षों को पत्र जारी कर सहयोग मांगा है।

हापुड़। हापुड़ में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रहेगी। बृहस्पतिवार रात उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पदाधिकारियों व अधिकारियों के बीच चली वार्ता में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर सहमति बनने के बाद हड़ताल वापस लेने पर सहमति बनी थी। लेकिन हापुड़ बार एसोसिएशन ने फिलहाल हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष एनुल हक ने इस संबंध में दूसरे जिलों की बार एसोसिएशन अध्यक्षों को पत्र जारी कर सहयोग मांगा है। पत्र में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल पर मनमाने ढंग से हापुड़ बार एसोसिएशन के पीड़ित अधिवक्ताओं को विश्वास में लिए बिना आंदोलन समाप्ति का निर्णय लेने का आरोप लगाया है। पत्र में उन्होंने कहा कि इस निर्णय से हापुड़ के अधिवक्ता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आरोपी अधिकारियों पर भी कार्रवाई का केवल आश्वासन ही मिला है। ऐसे में हापुड़ बार एसोसिएशन हड़ताल समाप्ति से सहमत नहीं है। उन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों की बार से आंदोलन में सहयोग मांगा है। शुक्रवार को अधिवक्ताओं की हापुड़ में हड़ताल जारी रहेगी। दोपहर में अधिवक्ता पैदल मार्च निकालेंगे।

भाजपा सांसद का रिश्तेदार बन होटल मालिक को दी धमकी

कौशांबी। होटल रेडिसन ब्लू के मालिक करन जैन और अन्य स्टाफ को दोपहर 12:30 बजे कुछ लोगों ने अभद्रता के बीच जान से मारने की धमकी दी। करन ने एक आरोपी गौरव अग्रवाल को भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल अग्रवाल का रिश्तेदार बताया है। होटल में अभद्रता और धमकी देने की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। आरोप है कि सांसद ने उन्हें फोन कर मामले में समझौते का दबाव बनाया। कौशांबी पुलिस ने दो नामजद समेत तीन पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर, सांसद ने आरोपों से इन्कार किया है। उन्होंने राजनैतिक छवि धूमिल करने का प्रयास वाला बताया। करन जैन ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे ऑफिस में काम कर रहे थे तभी स्टाफ के लोग दौड़कर उनके पास पहुंचे। बताया कि कुछ लोग होटल की महिला और अन्य स्टाफ से बदतमीजी कर रहे हैं। वह रिसेप्शन पर पहुंचे तो आरोपी सभी के ऊपर चिल्ला रहे थे। आरोपियों ने उन्हें देखा और अभद्रता की। आरोपियों ने शीशा तोड़कर सातवीं मंजिल से नीचे फेंकने की धमकी दी। आरोप यह भी है कि उन पर हमले का प्रयास किया लेकिन स्टाफ ने आरोपियों को रोक लिया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी दी। पांच आरोपियों में से दो लोगों की उन्होंने पहचान की।

एक आरोपी गौरव अग्रवाल था, जिसे भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल अग्रवाल का रिश्तेदार बताया जबकि दूसरा आरोपी दीपक अहलावत था। पुलिस को सूचना देने से पहले आरोपी होटल से चले गए।

मालिक से सांसद बोले- बातचीत कर लो, वरना वह किसी को नहीं रोक पाएंगे

आरोप है कि घटना के बाद होटल मालिक करन जैन के पास राज्यसभा सांसद ने फोन किया। उन्होंने आरोपियों से बातचीत के लिए कहा अन्यथा वो इन लोगों को नहीं रोक पाएंगे और ये किसी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने आरोपियों से खुद और परिवार की जान को खतरा बताया है। कौशांबी थाने में गौरव अग्रवाल, दीपक अहलावत और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कराया है।

राजनैतिक छवि धूमिल करने का प्रयास :

होटल मालिक की कॉल आने के बाद मैंने बैक कॉल की थी। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मैंने मामले में बातचीत करने के लिए कहा था। समझौते का दबाव बनाने के आरोप गलत हैं। मेरी राजनैतिक छवि धूमिल करने का प्रयास है। कुछ लोग लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह काम करा रहे हैं।

नामी प्रकाशन के नाम से नकली किताबें बेचीं, केस दर्ज

गाजियाबाद। रेलवे रोड बजरिया स्थित कॉलेज बुक डिपो पर नामी प्रकाशकों की नकली किताबें बेचने का मामला सामने आया है। मौके से पुलिस ने 350 नकली किताबें बरामद की है। दुकानदार अंकित कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। स्वर्णजयंतीपुरम निवासी संजीव कुमार राघव का कहना है कि मोहर कॉपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एस. चंद एंड कंपनी, नोएडा सेक्टर-63 स्थित भारती भवन पब्लिकेशन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, सेक्टर-62 नोएडा स्थित मैकगोहिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी दिल्ली स्थित स्पेक्ट्रम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड और दरियागंज दिल्ली स्थित जेपी ब्रदर्स मेडिकल पब्लिशर्स ने उन्हें नकली पुस्तकें बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई के लिए अधिकृत किया हुआ है। उन्हें सूचना मिली कि रेलवे रोड बजरिया स्थित कॉलेज बुक डिपो पर उपरोक्त प्रकाशकों की नकली किताबें बेची जा रही हैं, जिससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है। मौके पर पुलिस की मदद से पहुंचकर जांच कर किताबें बरामद की। दुकान में बैठे व्यक्ति ने नाम राइट गंज निवासी अंकित कुमार बताया। मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। एसीपी कोतवाली निमिष पाटिल का कहना है कि मामले में कॉपीराइट एक्ट की धारा में केस दर्ज किया गया है। आगे की जांच की जा रही है।

हिंडन एयरबेस में एयरबस सी-295 सैन्य विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे

परिवहन विशेष न्यूज

साहिबाबाद। स्पेन से आने वाले पहले एयरबस सी-295 सैन्य विमान की 25 सितंबर को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में भारत ड्रोन शक्ति कार्यक्रम में झलक दिखेगी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को विधिवत रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। वायुसेना के प्रवक्ता ने अगले सप्ताह तक इस विमान के हिंडन एयरबेस में पहुंचने के संकेत दिए हैं। वहीं, कार्यक्रम में 50 ड्रोन होंगे, जिन्हें 75 से ज्यादा एक्जिबिटर दिखाएंगे। इसकी खासियत होगी कि ड्रोन की हवाई उड़ान से लोग उनकी विशेषता देख पाएंगे। भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता के मुताबिक स्पेन से सी -295 टेक्निकल मिलिट्री एयर लिफ्ट विमान अगले एक सप्ताह में भारत पहुंच जाएगा। उसको हिंडन एयरबेस में 25 और 26 सितंबर को होने वाले भारत ड्रोन शक्ति कार्यक्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य अतिथि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना के प्रमुख वीआर चौधरी भी होंगे। यहां रक्षामंत्री सैन्य विमान की जानकारी लेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ वायुसेना को मजबूत करने के लिए बैठक में चर्चा भी कर सकते हैं।

हालांकि, अभी बैठक होना तय नहीं है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम में 50 ड्रोन की विशेषता हवाई उड़ान के दौरान देखने को मिलेगी। इसमें वो लोग शामिल होंगे जो भारतीय निर्माताओं के साथ काम करना चाहते हैं। सभी ड्रोन स्वदेशी होंगे। यह सैन्य क्षेत्र से लेकर सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, लोटरिग मुनिशन सिस्टम का प्रदर्शन, ड्रोन समूह और काउंटर ड्रोन के साथ-साथ 75 से अधिक स्टार्ट अप और कॉरपोरेट्स की भागीदारी होगी।

2025 तक आएंगे 16 विमान:

माना जा रहा है कि देश को दूसरा सैन्य एयरबस सी-295 विमान 2024 के मई महीने तक मिल सकता है। इसके बाद हर महीने एक विमान भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। 2025 तक भारतीय वायुसेना 16 विमानों के साथ देश का तिरंगा लहराएगी। 2030 तक 56 विमान वायुसेना को मिलेंगे। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना दुनिया में सी-295 के सबसे बड़े बेड़े का मालिक बन जाएगा। फिलहाल हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों ने भारत ड्रोन शक्ति कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है।

नगर निगम जल्द सरकार को भेजेगा कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव

गुरुग्राम। नगर निगम क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द सरकार को भेजने की तैयारी की जा रही है। निर्धारित मानकों का पालन करने वाली कॉलोनियों की बृहस्पतिवार को निगम आयुक्त पीसी मीणा ने समीक्षा की। नगर निगम क्षेत्र में करीब 80 कॉलोनियां अनधिकृत चिह्नित की गई थीं। इसके साथ ही शहर में स्ट्रीट लाइटों के बेहतर रखरखाव के लिए अधिकारी तैनात होंगे। शहर के चारों जोन में पुस्तकालय बनाने और हरियाली क्षेत्र बढ़ाने के फैसले भी नगर निगम ने लिए हैं।

बृहस्पतिवार को अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने कहा कि वह कॉलोनियां जो निर्धारित मापदंडों को पूरा करती हैं, उनका प्रस्ताव जल्द से जल्द सरकार को भेजें, जिससे सरकार उनके बारे में अधिसूचना जारी कर सके। उन्होंने कहा कि शहर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सही प्रकार से रहे, इसके लिए बेहतर प्रबंध करना सुनिश्चित करें। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं की जानी हैं, उन्हें जल्द किया जाए।

पीसी मीणा ने कहा कि शहरी निकाय स्वामित्व योजना मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समयावधि में यह पूरा हो। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। अगर किसी अधिकारी की कोताही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिकारी एक-एक आवेदन को ध्यानपूर्वक चेक करें तथा उस पर जल्द निर्णय लें। अगर कोई आवेदन निरस्त किया जाना है, तो उसे उचित कारण के साथ ही निरस्त करें। निगम क्षेत्र के प्रत्येक जोन में पुस्तकालय स्थापित करने राजस्व शाखा को स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़क निर्माण के साथ ही ग्रीन बेल्ट और लैंड स्केपिंग का काम हो

शहर में हरियाली बढ़ाने तथा ग्रीन बेल्टों का बेहतर विकास करने के लिए निगम आयुक्त ने सभी ग्रीन बेल्टों में पर्याप्त सफाई व प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के समय ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ व लैंड स्केपिंग भी साथ-साथ की जाए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते ग्रीन बेल्ट क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की बेहतर योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सोहना रोड़, व राष्ट्रीय राजमार्ग के फ्लाई ओवर के नीचे ग्रीन बेल्ट व स्पोर्ट्स की सुविधाएं विकसित करने बारे भी अधिकारियों से कहा है। इसके साथ ही बागवानी कचरे का सामान निकालने, कुछ मॉडल पार्क विकसित करने तथा पार्कों का बेहतर सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए हैं।

पीएम स्वनिधि योजना के लाभपात्रों की श्रेणी को बढ़ाया

पीएम स्वनिधि की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि योजना के लाभ पात्रों की श्रेणी को बढ़ा दिया गया है। अब समाचार पत्र हॉकर, लॉन्ड्री का काम करने वाले, केबल टीवी ऑपरेटर, साइकिल मरम्मत करने वाले, कारपेंटर, कोरियर सर्विस, हेयर ड्रेसिंग, ताले-चाबी का कार्य करने वाले, मोची, गाड़ियों की सफाई करने वाले, पैकिंग व पैकेजिंग का काम करने वाले, जूते पॉलिश करने वाले, ऑटोमोबाइल सर्विस, कपड़े डाई करने वाले, बुक बाईंडिंग, टेंट तथा फोटोकॉपी व लेमीनेशन संबंधी कार्य करने वाले भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

25 लाख रुपये तक की कीमत में जल्द लॉन्च होने को तैयार, ये पांच इलेक्ट्रिक एसयूवी, जानें डिटेल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में जल्द ही पांच नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारतीय बाजार में लॉन्च करने तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक किस कंपनी की ओर से किस एसयूवी को इलेक्ट्रिक वर्जन में लाया जा सकता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

टाटा पंच ईवी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा की ओर से माइक्रो एसयूवी पंच को इलेक्ट्रिक वर्जन में लाने की तैयारी की जा रही है। इस एसयूवी को सिट्रॉएन ईसी3 और एमजी कॉमेट के सेगमेंट में लाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इसे अगले साल की शुरुआत में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है।

ह्यूंदै क्रेटा ईवी

ह्यूंदै की ओर से भी क्रेटा के ईवी वर्जन को लाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में कई बार इस एसयूवी को टेस्ट करते हुए देखा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी में 100 किलोवाट की मोटर के साथ 39 .2 किलोवाट आवर की बैटरी मिल सकती है। जिससे एसयूवी को करीब 450 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

टाटा कर्व ईवी

टाटा की ओर से ही कर्व ईवी को भी भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से इस एसयूवी को भी अगले साल तक लॉन्च किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी में कंपनी की ओर से 500 किलोमीटर तक की रेंज दी जा सकती है। साथ ही इसे नेक्सन से ऊपर पोजिशन किया जा सकता है।

महिंद्रा एक्सयूवी ई8

महिंद्रा की ओर से भी एक्सयूवी ई8 को भारतीय बाजार में अगले साल तक लॉन्च किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक यह एक्सयूवी 700 का इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकती है। जिसमें कंपनी की ओर से 60 से 80 किलोवाटर आवर का बैटरी पैक दिया जा सकता है। जिससे इस एसयूवी को करीब 400 से 500 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है।

मारुति ईवीएक्स

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति की ओर से ईवीएक्स इलेक्ट्रिक एसयूवी को भी अगले साल तक भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी को जनवरी में हुए ऑटो एक्सपो में पेश किया था। जानकारी के मुताबिक इसमें 550 किलोमीटर की रेंज और 60 किलोवाट आवर तक की क्षमता की बैटरी को दिया जा सकता है।

इन इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलता है भरपूर सामान रखने का स्पेस ओला से लेकर हीरो तक इस लिस्ट में शामिल

आज हम आपके लिए बेस्ट बूट स्पेस से लैस इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट लेकर आए हैं।इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस के साथ ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है । इस स्कूटर में कुल 43 लीटर का बूट स्पेस मिलता है सेफ्टी के मामले में भी यह काफी दमदार है। भारतीय बाजार में सबसे अधिक सेल इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला की ही होती है ।

आज के समय में आसपास जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है । इसमें न केवल आपके पैसों की बचत होती है बल्कि समय की भी बचत होती है। अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर से कहीं भी आते जाते हैं और सामान रखने की आपको आदत है तो आज हम आपके लिए बेस्ट बूट स्पेस से लैस इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट लेकर आए हैं। इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस के साथ ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है । इस स्कूटर में कुल 43 लीटर का बूट स्पेस मिलता है सेफ्टी के मामले में भी यह काफी दमदार है। इसके साथ ही इसकी रेंज भी काफी बढ़िया है।

ओला एस 1 प्रो

भारतीय बाजार में सबसे अधिक सेल इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला की ही होती है ।आपको बता दे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको कल 36 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा।

ओला एस1 प्रो जेन 2 एयर

हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर ओला का ही स्कूटर है। यह नए और शानदार टेक्नोलॉजी से लैस है इसमें आपको काफी स्टोरेज भी मिल जाता है। इस स्कूटर में कुल 34 लीटर का स्टोरेज मिलता है।

सिम्पल वन

यह इलेक्ट्रिक स्कूटर खोल दो बैटरी बैक के साथ आता है इसके बाद भी इस स्कूटर में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इसमें कुल 30 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

हीरो वीदा वी 1

हीरो का यह सबसे के फायदे इलेक्ट्रिक स्कूटर है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 26 लीटर तक का बूट स्पेस मिल जाएगा। स्टोरेज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसमें आराम से एक हेलमेट तो रख ही सकते हैं।

जी-20 और भारत का विपक्ष

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

जी-20 की अध्यक्षता भारत को एक साल पहले मिली थी और सितम्बर 2023 को उसका समापन कार्यक्रम दिल्ली में तय हो चुका था जिसमें सभी देशों के राज्याध्यक्षों को आना था। जिस तरह से देश में वर्ष भर जी-20 की उपयोगिता, उसकी महत्ता और पूरे विश्व के एकात्म भविष्य का रास्ता खोजने के लिए चिन्तन होता रहा...

यही कारण था कि जब दुनिया के बाकी देश दिल्ली में आकर भारत की प्रशंसा कर रहे थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अपने सनातनी हिंदू होने पर गर्व कर रहे थे, तब राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि के तौर पर विदेशों में जाकर बता रहे थे कि यदि भारत में इसी प्रकार चलता रहा तो देश का पतन हो जाएगा। उनको वही भारत चाहिए था जो अंग्रेज छोड़ कर गए थे। राहुल एक बार महात्मा गांधी का हिंद स्वराज पढ़ लें तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा'

जी-20 की अध्यक्षता भारत को एक साल पहले मिली थी और सितम्बर 2023 को उसका समापन कार्यक्रम दिल्ली में तय हो चुका था जिसमें सभी देशों के राज्याध्यक्षों को आना था। जिस तरह से देश में वर्ष भर जी-20 की उपयोगिता, उसकी महत्ता और पूरे विश्व के एकात्म भविष्य का रास्ता खोजने के लिए चिन्तन होता रहा, उससे यह स्पष्ट होने लगा था कि भारत एक बार फिर से विश्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार हो रहा है। जी-20 के लोगो 'वसुधैव कुटुम्बकम' से ही संकेत मिलने लगे थे कि अब भारत अपनी संस्कृति, धरोहर व दर्शन को लेकर एपोलोजेटिक नहीं है, बल्कि उस पर गर्व कर रहा है। जिस प्रकार भारत मंडपम्का निर्माण कार्य चल रहा था और वह भारत की सनातन धरोहर के रूप में उभर रहा था, उससे भारत के 'राज परिवार' को यह संकेत तो मिलने शुरू हो ही गए थे कि भविष्य का भारत अपने सनातन धरातल पर खड़ा होने जा रहा है। पिछले हजार साल से अरबों, तुर्कों, मुगलों (यानी एटीएम), पुर्तगालियों, डचों, फ्रांसीसियों व अंग्रेजों यानी एंग्लो सैक्सनों ने (यह संयोग है कि इसमें इटली शामिल नहीं था) इसी सनातन भारत को नष्ट करने का प्रयास किया था। भारत फिर से उठ रहा था। जी-20 में उसे पूरा विश्व देखने वाला था। लेकिन भारत के विपक्ष को भी भारत के इस अभ्युदय को रोकने का हर प्रयास करना था। विपक्ष अभी भी उसी इंडिया से चिपका रहना चाहता है जो एटीएम और पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस (यानी पीईएफ) छोड़ कर गए थे। एटीएम और पीईएफ का दुर्भाग्य है कि किसी देश पर कब्जा करने के पुराने तौर तरीके खत्म हो गए हैं।

आज का युग हाईब्रिड वार का है। इसमें सेनाएं भेजने की जरूरत नहीं होती, बल्कि नैरेटिव गढ़े जाते हैं। वे नैरेटिव इंडिया में स्थापित किए जाते हैं। इंडिया के ही कुछ लोग उसे अपने चिन्तन का आधार बना लेते हैं और इन विदेशी नैरेटिवों या आख्यानों से सनातन भारत के नैरेटिव को ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। यह भारत में एटीएम और पीईएफ के अधूरे एजेंडे को इंडिया द्वारा ही पूरा करने की हाईब्रिड रणनीति कही जा सकती है। कांग्रेस के राजपरिवार के लिए लाजिमी था कि इस रणनीति पर जी-20 के समापन से पहले ही अमल करना शुरू कर दिया जाए, ताकि जब देश जी-20 के महासम्मेलन के अवसर पर दुनिया की राजनीति में भारत का नव उदय देख रहा हो तो इंडिया के आवरण तले सनातन भारत को चुनौती दी जा सके। समय व दिन तय थे। जी-20 का महासम्मेलन सितम्बर 2023 में होने वाला था। नया महाभारत होने वाला था। हजारों हजारों साल पहले धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था, 'मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया?' भारत के पांडुपुत्र तो महासम्मेलन की तैयारी कर रहे थे। उधर पटना, बेंगलुरू में इंडिया भी तैयारी में जुट गया था। पटना व बेंगलुरू में स्वयं को भारत की सत्ता का वंशों के आधार पर दावेदार मानने वाले राजपरिवार तो जुलाई 2023 को जुटने शुरू हुए थे, लेकिन अपने एजेंडे पर इस 'इंडिया' के अलग-अलग घटकों ने अपने एजेंडे पर काम इससे भी कई महीने पहले ही काम शुरू कर दिया था। तमिलनाडु में प्रोग्रेसिव लेखकों के बैनर तले 'सनातन भारतीय संस्कृति उन्मूलन' सम्मेलन की तैयारियां तो मार्च अप्रैल में ही शुरू हो गई थी। तमिलनाडु में सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान भी शुरू हो गया था। डीएमके का राजपरिवार सनातन के उन्मूलन के लिए लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में किन शब्दों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इसकी खोज में जुट गया था। शायद इसके लिए 'इंडिया' का पूरा थिंक टैंक ही जुट गया हो। हो सकता है इसके लिए इंडिया के आवरण के नीचे जुटने वाले अन्य घटकों या राजपरिवारों से भी सलाह मशविरा किया गया हो। यही कारण है कि सनातन भारतीय धरोहर को कोरोना, डेंगू, मलेरिया के समकक्ष स्थापित किया गया।

इंडिया के आवरण तले करुणानिधि का राजपरिवार इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए यहां तक पहुंच गया कि सनातन का केवल विरोध ही नहीं करना है, बल्कि उसका समूल नाश तक करना है। इंडिया के बाकी घटकों ने सनातन के समूल नाश के नैरेटिव को बहुत ही चालाकी से देश भर में आगे बढ़ाया। उन्होंने तमिलनाडु के इस राजपरिवार के इस नैरेटिव को मजहब से जोड़ कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। उनकी व्याख्या थी कि राजपरिवार के प्रतिनिधि उदयनिधि भारतीय/हिन्दु समाज के भीतर की कुरीतियों को नष्ट करने की बात कह रहे थे। लेकिन इंडिया राजपरिवार जिसे नेहरु-गान्धी के ब्रांड नाम से जाना जाता है, वह भारत की सनातन धरोहर से इतना दूर जा चुका है कि उसे शायद हिन्दु समाज की कुरीतियों का पता भी नहीं है। सनातन उन्मूलन आन्दोलन की व्याख्या भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि सनातन धर्म और हिन्दु धर्म दोनों अलग-अलग हैं। राहुल गान्धी सनातन धर्म और हिन्दु धर्म को अलग-अलग समझें, यह बात समझ में आती है। उनसे इस प्रकार की गहरी बातों की समझ की आशा भी नहीं की जा सकती। धर्म तो होता ही सनातन है। न्यायाधीश का धर्म बिना लालच और भय के न्याय करना है। यह धर्म समय के अनुसार बदल थोड़ा जाएगा। माता-पिता का धर्म अपने बच्चों का पालन करना है और बच्चों का धर्म बुढ़ापे में अपने माता-पिता की सेवा करना है। यह धर्म तो सनातन ही है। अन्याय का विरोध करना चाहिए, यह सभी का धर्म है। यह धर्म तो सनातन ही है। कर्मकांड या रिचुइलज का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। कर्मकांड का संबंध मजहब से है। जब कर्मकांड रूढ़ हो जाते हैं तो वे कुरीतियों में बदल जाते हैं। कुरीतियों को दूर करना ही चाहिए। जाति-पांति भारत के एक हिस्से के लोगों की सामाजिक संरचना है। लेकिन यह सारे भारतीय/हिन्दु समाज का हिस्सा नहीं है। लेकिन सामाजिक संरचना का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन धर्म है ही सनातन। इसी सनातन धर्म को भारत में हिन्दु धर्म कहा जाता है। धर्म का किसी सम्प्रदाय या मजहब से कोई संबंध नहीं है। इंडिया गठबन्धन के घटक सनातन के उन्मूलन को अपना एजेंडा घोषित कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस को पता ही था कि जी-20 का महासम्मेलन किस तिथि को होने वाला है। इस महासम्मेलन में भारत का गौरव बढ़ेगा। कांग्रेस को पता था कि देश के भीतर वह इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए 'इंडिया' गठबंधन की रणनीति यह बनी कि इसका मुकाबला देश से बाहर जाकर किया जाए। राहुल गान्धी ने इसी रणनीति के तहत जी-20 के महासम्मेलन के दौरान विदेशों में जाकर मोर्चा सम्भाला। यही कारण था कि जब दुनिया के बाकी देश दिल्ली में आकर भारत की प्रशंसा कर रहे थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अपने सनातनी हिन्दु होने पर गर्व कर रहे थे, तब राहुल गान्धी इंडिया गठबन्धन के प्रतिनिधि के तौर पर विदेशों में जाकर बता रहे थे कि यदि भारत में इसी प्रकार चलता रहा तो देश का पतन हो जाएगा। उनको वही भारत चाहिए था जो अंग्रेज छोड़ कर गए थे। राहुल गान्धी का कहना है कि उन्होंने वेद, उपनिषद और गीता इत्यादि सब पढ़ लिए हैं, लेकिन उन्हें उसमें कहीं भी आज का हिन्दु धर्म नहीं मिला। वे केवल एक बार महात्मा गान्धी का हिन्द स्वराज पढ़ लें तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या इंडिया के पास भारत को पढने व समझने का समय है?

संपादक की कलम से

फिल्म से कहीं ज्यादा

देश की वास्तविकता को देश कितना देखता है या हकीकत से रूबरू होने के लिए मीडिया पर कितना भरोसा करें, यह बहस का विषय अब रहा नहीं। पिछले कुछ सालों में हमने जो देखा, वह सुनाई नहीं दिया और जो मीडिया ने सुनाया, उसे सुनकर कान बहरे और दृष्टि कमजोर होती गई। ऐसे में नागरिक के सवाल लाभार्थी होने की मचान पर चले गए, जबकि देश का गुणगान करना हमारी व्यथा हो गई। इस दौरान दिखाने वाल मीडिया, पढ़ाने वाली पत्रकारिता और समाज के मनोरंजन में नफरत का बाजार गर्म करने वाला फिल्म जगत इतना परवान चढ़ गया कि फिल्में सियासत की तिजोरी को गर्म करने लगीं या लोगों को भीड़ बनाकर जोतने लगीं। जहां कहने की बात सुनने की फिरौती बन जाए या देश एक तरह के राग द्वेष में पहेलियों के अर्थ बदलने लगे, वहां एक सच्ची अभिव्यक्ति की जरूरत थी, जिसे पूरा करने की वजह से देशभर में 'विक्रम राठौड़' जीत रहा है। यह विक्रम राठौर पिछले कुछ वर्षों से नदारद था या इसे हमारी व्यवस्था ने ही कहीं कैद करके रखा था। यह 'विक्रम राठौर' हमारे भीतर भी था। मीडिया के भीतर भी था और फिल्मों के विषयों में भी था, लेकिन हम सभी ने पिंजरे बना लिए थे। इस 'विक्रम राठौर' को शाहरुख खान ने अपनी ताजातरीन फिल्म 'जवान' में जिंदा कर दिया है।

यह फिल्म वही सब कुछ बोल रही है, जो हमारे कानों में पहले से मौजूद है। यह वही दिखा रही है, जो हमारी लोकतांत्रिक आंखें देख रही हैं। 'जवान' फिल्म खेत में किसान को, बैंक में आम उपभोक्ता को व चुनाव में ईवीएम मशीन के जरिए आम मतदाता के साथ बोल रही है। फिल्म का एक व्यावसायिक पक्ष रहा होगा या फिल्म इंडस्ट्री के बासीपन को मिटाने की भूख रही होगी, लेकिन देश में 'वक्त' की सही परिस्थिति का मुआयना अगर 'जवान' के जरिए हो रहा है, तो यह कालखंड याद किया जा रहा है। फिल्म दर्शक अभी कुछ दिन पहले तक एक खास मजमून की तलाश में इतिहास देख रहे थे, लेकिन 'जवान' के माध्यम से वे हकीकत से रूबरू होने के लिए थियेटर से वास्तविकता के शब्द खोज रहे हैं। यह नागरिक संवाद की नई परिभाषा है जो फिल्मी पर्दे पर एक जुनून की तरह चिन्हित है। हम इसे महज फिल्म या फिल्म का क्रॉफ्ट मानें, लेकिन विषयों की तीव्रता में जिस हिंदोस्तान को शाहरुख खान दिखा रहे हैं, वहां फिल्म से कहीं ज्यादा देश की समीक्षा हो रही है। देश की समीक्षा में किसानों की आत्महत्या के कारण दिखाई दे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति दिखाई दे रही है, तो ऑक्सीजन को तड़पती लाशों के बीच भी गुनाह ढूंढने की व्यवस्था में कोई निर्दोष शहीद हो रहा है।

व्यवस्था के दागों पर फिल्म की टिप्पणियां रौंगटे खड़े कर देती हैं, तो क्या वहां दर्शक सिर्फ फिल्म देख रहा है। यकीनन नहीं क्योंकि वहां वह व्यवस्था की आंच में खुद को टटोल रहा है। फिल्म के कथानक में व्यवस्था के साक्ष्य दर्शक को नागरिक समाज बना रहे हैं, इसलिए वहां सूचना के अवरुद्ध लिफाफे खुल रहे हैं। कम से कम इस फिल्म ने मीडिया के आचरण और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को शीशे पर उतार दिया है। यह वह सच है जिससे कोसों दूर बैठ चुके मीडिया ने अपने दायित्व से कन्नी काट ली है। हम फिल्म को फिल्म की तरह नहीं देख रहे, लेकिन फिल्म से मिले 'विक्रम राठौर' के चरित्र से यह उम्मीद रखते हैं कि अब गूंगे हो चुके समाज की अंगुलियों पर लोकतंत्र के प्रश्न और व्यवस्था से पूछने का साहस पैदा होगा। मुंबई फिल्म उद्योग से निकला यह साहसिक कदम उस 'भारत' के करीब पहुंच रहा है, जिसकी खातिर हम सभी आजाद हुए या जिसकी मर्यादा के लिए हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया।

राय

यह कैसा विशेष सत्र

'खोदा पहाड़, निकली चुहिया और वह भी मरी हुई'।' संसद के विशेष सत्र की घोषित कार्यसूची पर यह कहावत सटीक बैठती है। मोदी सरकार ने अचानक संसद सत्र की घोषणा की थी, जबकि मानसून सत्र 11 अगस्त को ही स्थगित किया गया था। परंपरा के मुताबिक अब शीतकालीन सत्र आना है। सरकार या तो घोषित करे कि शीतकालीन सत्र नहीं होगा। फिर सवाल है कि लेखानुदान कब पारित किया जाएगा? संपूर्ण बजट तो नई सरकार बनने के बाद ही पारित किया जा सकता है। यदि पारित आर्थिक बजट नहीं होंगे, तो सरकार खर्च कैसे चलाएगी और सरकारी अफसरों, कर्मचारियों के वेतन कैसे दिए जाएंगे? संवैधानिक वर्ग के पदेन चेहरों के वेतन-भत्ते भी लटक कर रह जाएंगे। हमारी व्यवस्था संसदीय कार्यवाही और उसके निर्णयों पर ही आश्रित है। बहरहाल 13 सितंबर को संसद सत्र की कार्यसूची जारी की गई। 17 सितंबर को सर्वदलीय औपचारिक बैठक है। इसी दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिवस और 'विश्वकर्मा जयंती' है। प्रधानमंत्री नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' फहराएंगे। ध्वजारोहण के बाद ही संसद में कामकाज शुरू होगा, क्योंकि देश के 'फ्लैग कोड' के मुताबिक, किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही यह दर्जा मिल पाता है। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र आरंभ होगा। हालांकि यह संयुक्त अधिवेशन के बजाय 'संयुक्त आयोजन' के रूप में आहूत किया जाएगा। उस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित रह सकती हैं। इसे राष्ट्रपति की 'गरिमामय मौजूदगी' कहा गया है। गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को नए संसद भवन में कामकाज आरंभ किया जाएगा। बहरहाल सत्र में कुल चार बिल पारित किए जाने हैं। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा-शर्तों वाला बिल है, जिसे मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। इस संदर्भ में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और संवैधानिक पीठ का भारत सरकार पर दबाव था कि चुनाव आयुक्तों को चुनने की एक संवैधानिक प्रक्रिया होनी चाहिए। सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी चुनाव आयुक्त नहीं बना सकती। सर्वोच्च अदालत का सुझाव था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधान न्यायाधीश मिलकर चयन करें कि कौन चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। मोदी सरकार ने इस फॉर्मूले को खारिज कर अपना ही पैनल बनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष होंगे। कोई भी कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री की मानसिक पसंद और उनके फैसले के खिलाफ जाने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? लोकसभा में फिलहाल नेता प्रतिपक्ष नहीं है। अलबत्ता विपक्ष में कांग्रेस संसदीय दल सबसे बड़ा है, लिहाजा उसके नेता अधीर रंजन चौधरी को ऐसे पैनल में रखा जाता है। यह उन पर है कि वह शामिल होते हैं अथवा नहीं। संभावना है कि संसद में यह बिल पारित होने के बावजूद सर्वोच्च अदालत की न्यायिक पीठ संवैधानिक समीक्षा के नाम पर हस्तक्षेप कर सकती है। बहरहाल इसके अलावा, अधिवक्ता संशोधन बिल और प्रेस एवं सावधि प्रकाशनों के पंजीकरण का संशोधन बिल मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पारित किए जा चुके हैं। डाकघर संशोधन बिल भी मानसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया जा चुका है। हमारा मानना है कि ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में भी पारित किए जा सकते थे। इनकी न्यूनतम अवधि 6 माह है और अभी सरकार भी नहीं बदली है। लोकसभा और राज्यसभा के सदन यथावत निरंतर हैं, लिहाजा इन बिलों के संदर्भ में ऐसी कोई तात्कालिक संवैधानिक अड़चन दिखाई नहीं देती कि संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ा।

पहाड़ों का हमदर्द बनना होगा

प्रताप सिंह पटियाल

भावी पीढ़ियों के सुखमय जीवन व पर्वतों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पहाड़ों का हमदर्द बनना होगा, ताकि देवभूमि की फिजाओं में अमन की शमां जलती रहे। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के विकल्प तलाशने होंगे'

धरती के सीने पर कुदरत की भव्य संरचना पहाड़ मजबूती व निर्भीकता का प्रतीक होते हैं। 'हुस्न पहाड़ों का' भारत की मारूफ गुलुकारा लता मंगेशकर द्वारा गाया यह मशहूर नगमा पहाड़ों की शबाहत को जाहिर करता है, मगर आलम यह है कि पर्यटन, आस्था व सुकून का केन्द्र रहे पहाड़ संकट के बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। गहरे जख्म देने वाली कुछ अफसोसनाक तारीखें एक मुद्दत गुजर जाने के बाद भी नहीं मिटती। आसमान से आफत बनकर बरसी बरसात व दरकते पहाड़ों ने हिमाचल की भोली-भाली विरासत के लोगों को कभी न भूलने वाले गहरे घाव दिए हैं। मगर गुजरी हुई शब का मातम मनाने से कुछ हासिल नहीं होता। कामयाबी का मुनासिब मुकाम हासिल करने के लिए नई सहर के उगते हुए आफताब से निगाहें मिलाकर चलना पड़ता है। मुश्किल वक्त की चुनौतियों को हौसले की बुनियाद पर ही फतह किया जा सकता है। विडंबना है कि पर्यटन क्षेत्र से लेकर देश की उन्नति से जुड़े मुद्दों पर मुल्क के हुक्मरानों की निगाहों का मरकज हमेशा पहाड़ ही बने हैं। पहाड़ों के पानी ने देश की तकदीर व तस्वीर बदल कर विकास के बेमिसाल मजमून लिखकर आलमी सतह पर देश का मान बढ़ाया है, तो पहाड़ की जवानी देशरक्षा के महाज पर राष्ट्र के लिए ही समर्पित रही है।

1960 का दशक, जब देश की करोड़ों आबादी पेयजल के संकट से जूझ रही थी, लोग बिजली से महरूम थे, 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों में देश की मईशत चरमरा चुकी थी, मुल्क खाद्यान्न की भारी किल्लत से जूझ रहा है, उस वक्त मुल्क के हुक्मरानों ने उन चुनौतियों से निपटने के लिए भाखड़ा बांध व पौंग डैम की संगे बुनियाद हिमाचल की सरजमीं पर रखी थी। बांधों के पानी से उत्पन्न बिजली से पड़ोसी सूबे अफरोज हुए। पड़ोसी राज्यों की मरूस्थलीय भूमि शादाब हुई। हरित क्रांति का आगाज हुआ, मगर उस कुर्बानी का नजराना हिमाचल के हजारों परिवारों को विस्थापन के रूप में मिला। बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा के सैकड़ों गांवों की इन जलाशयों में जल समाधि दे दी गई। बिलासपुर में चंदेल राजवंश की कहलूर रियासत की राजधानी गोविंद सागर झील की आगोश में समा गई। प्रदेश में कीरतपुर-मनाली जैसे फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्गों व कई पुलों तथा सुंरगों का निर्माण हो रहा है। रेलवे लाइन की बिसात बिछ रही है। इन विकास कार्यों का सीधा संबंध देश के रक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए है ताकि लेह, लद्दाख व सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भारतीय सेना की पहुंच आसान हो सके। परंतु इन विकास कार्यों के चलते राज्य के सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं।

बेशक विकास व उन्नति वक्त का तकाजा है। बढ़ती आबादी व सडक़ों पर वाहनों की तादाद में इजाफा तथा देश की सरहदों के उस पार भारत को दहलाने का मंसूबा तैयार करने वाले चीन व पाकिस्तान जैसे मुल्कों से निपटने के पेशेनजर सडक़ निर्माण कार्य सरकारों की प्राथमिकता में होने चाहिए। लेकिन ऐसा विकास जो लोगों के आशियाने छीनकर मौत के साए में जीने को मजबूर कर दे, पहाड़ों को खोखला करके तबाही का खौफनाक मंजर पेश करे, प्राकृतिक संसाधनों का वजूद मिटाकर लोगों को पेयजल के लिए फरियादी बना दे, लोग शरणार्थी बनकर हाथों में ज्ञापन लेकर शासन-प्रशासन के पास अपने हकूक की गुहार लगाने को मजबूर हो जाएं, ऐसे निर्माण कार्यों का मॉडल हरगिज बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। जबरन विकास की जद्दोजहद से दरकते पहाड़ अब मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। पहाड़ों का दरकना कोई इत्तेफाक नहीं है। मशीनीकरण द्वारा प्रकृति से हो रहा खिलवाड़ तथा बेलगाम रफ्तार से हो रहे निर्माण कार्य भी आपदाओं के लिए काफी हद तक जिम्मेवार हैं। पहाड़ों की संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की शैली पहाड़ों की भौगौलिक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। मगर पहाड़ों में भी मैदानी इलाकों की तर्ज पर बेलगाम निर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। आपदाएं कुदरत का कहर बनकर आएं या मानव दखल से घटित हों, परिणाम विनाशजनक होता है। पहाड़ों के बिखरते वजूद के साथ लोगों के टूटते ख्वाब व सुलगती तन्हाइयां आपदाओं की शदीद गर्दिश को बयान कर रही हैं। अतः मरकजी हुकूमत के वजीरों को मुश्किल दौर से गुजर रहे हिमाचल के जमीनी हालात से मुखातिब होकर राज्य की मदद के लिए आगे आना होगा। यह सियासी मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के स्वाभिमान के लिए कुर्बानियों का इतिहास लिखने वाले राज्य पर आई खौफनाक त्रासदी की दास्तान है। विकास कार्यों में मशगूल व्यवस्थाओं तथा आधुनिकता की चकाचौंध में भौतिकतावाद की बढ़ रही ललक में मशरूफ लोगों को समझना होगा कि कुदरत का भी अपना एक निजाम है। कुछ कायदे कानून हैं। पहाड़ों की भी एक सलाहियत है। कुदरत के असूलों को ताक पर रखकर निर्माण कार्यों में आजमाईश किए जा रहे तौर तरीके भविष्य में खतरनाक साबित हो सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण को लेकर अदालतों के फरमान, एनजीटी की हिदायतें, पर्यावरणविदों की नसीहत व भूगर्भ शास्त्रियों की राय तथा अन्य विशेषज्ञों की चेतावनियों को संजीदगी से लेना चाहिए। आपदाओं की मार झेल रहे हिमाचल को हिम्मत व जज्बे के साथ उठना होगा। संघर्ष रणभूमि में हो या मनभूमि में, जीने की तलब व उम्मीदों को जिंदा रखने तथा कामयाबी का अध्याय लिखने के लिए हर मैदान में धैर्य व जज्बे की जरूरत होती है। चूंकि आंधियों का सफर ज्यादा लंबा नहीं चलता। दौर हमेशा हवाओं का ही कायम रहता है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ वीरभूमि के नाम से विख्यात है। चुनौतियों से निपटने में पहाड़ के मेहनतकश लोगों का व्यापक इतिहास रहा है। बहरहाल अपने दीदार मात्र से अशांत मन को आध्यात्मिक सुकून का एहसास कराने वाले पहाड़ आखिर सुकून-ए-हयात छीनने पर आमादा क्यों हैं, यह वैज्ञानिक मंथन का विषय है। भावी पीढियों के सुखमय जीवन व पर्वतों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पहाड़ों का हमदर्द बनना होगा, ताकि देवभूमि की फिजाओं में अमन की शमां जलती रहे। दरकते पहाड़ों का समाधान व प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के विकल्प तलाशने होंगे। आक्रोश का इजहार कर रही प्रकृति के साथ अदब से पेश आना होगा।

हास्य चिंतन

हिंदी पखोड़े का पकौड़ा!

घर से बाहर निकला तो सामने शास्त्रीजी के लॉन में टैंट लगा हुआ था। शास्त्रीजी कुछ काम कर रहे थे। जिज्ञासावश मैं अंदर लॉन में गया तो भट्टी पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी और हलवाई पकौड़े तल रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है? मैंने शास्त्रीजी से ही पूछा - 'शास्त्रीजी, आज क्या प्रोग्राम है? पकौड़े कैसे तले जा रहे हैं?' शास्त्रीजी मेरे पास ही आ गए और बोले - 'शर्मा जी, आपको कुछ भी पता नहीं होता। अरे भाई आज से हिंदी पखोड़ा (पखवाड़ा) शुरू हो गया है। अभी शाम को हिंदी के उन्नयन के लिए संगोष्ठी होगी, तत्पश्चात हिंदी सेवियों के लिए पकौड़ा-जलेबी का हैवी नाश्ता दिया जाएगा।' मैंने कहा - 'लेकिन हिंदी उन्नयन और पकौड़ा-जलेबी का तालमेल मेरी समझ में नहीं आ रहा?' वे हंसने लगे और बोले - 'मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का प्रधानमंत्री हूं और विगत चालीस वर्षों से मैं यह अनुष्ठान करता आ रहा हूं। हिंदी के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है।' मैं बोला - 'लेकिन उन्नयन में, यह भी अजब-गजब है।'

वे बोले - 'ये सब हिंदी की देन है। सरकार हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए इतना अनुदान संस्था को देती है कि मैं असली घी का गाजर का हलवा भी खिलाता रहूं तो पूरे वर्ष राशि खत्म नहीं हो।' मैंने कहा - 'लेकिन आपके दोनों बेटे अंग्रेजी माध्यम से पढक़र ही आगे बढ़ पाए हैं। इसमें हिंदी का कोई योगदान न आपने लिया, न हिंदी ने दिया।' वे बोले - 'शर्मा जी, वे अंग्रेजी से राइज कर पाए और मैं हिंदी से, फर्क इतना सा है। बाकी कोई अंतर है नहीं।' मैं बोला - 'मेरा मतलब वे भी तो हिंदी सेवी हो सकते थे।' शास्त्री ने बात को विराम देने के लिहाज से कहा - 'शर्मा जी, छोड़िए इस मुद्दे को। यह लंबी बहस की बात है। आप तो आइए और हिंदी का पकौड़ा भरपेट खाइए।' यह कहकर वे एक खाली प्लेट लेकर पकौड़े लेने चले गए। तभी वहां अन्य हिंदी सेवियों का भी आगमन शुरू हो गया। थोड़ी देर में तो पांडाल में हिंदी सेवियों की पूरी जमात आ इक_ा हुई। वे सब प्लेटों में जलेबी-पकौड़ा भर-भर कर गरमा-गर्म बातचीत के बीच पेट भराई में जुटे थे। शास्त्रीजी ने एक प्लेट भरकर मुझे भी पकड़ा दी। जाते-जाते बोले - 'मुझे पता है शर्मा जी, हिंदी सेवा को लेकर आपके मन में द्वंद्व छिड़ा हुआ है।

उसके लिए पूरा पखोड़ा पड़ा है, आज केवल पकौड़ा।' यह कहकर वे चले गए। मेरे पास एक बुजुर्ग सज्जन खड़े हुऐ थे तथा प्लेट खाली कर रहे थे, मैंने उन्हीं से पूछा - 'क्यों सर, आप कब से हिंदी सेवा से जुड़े हुए हैं।' उनके पास भी वक्त नहीं था, वे बोले - 'आधा घंटे बाद बात करेंगे, फिलहाल केवल पकौड़ा।' मैं चुप हो गया। मैंने भी प्लेट सलटाने का कार्य शुरू किया तो पाया कि हिंदी सेवा का पकौड़ा बेहद स्वादिष्ट था। तभी एक सज्जन मेरे पास आए और बोले - 'माफ करिए, आपको पहले कभी नहीं देखा। आपका परिचय?' मैं बोला - 'मैं शास्त्रीजी का पड़ौसी हूं। मेरी नौकरी बाहर थी। वर्षों से बाहर था, इसी साल घर लौटा हूं। शास्त्री जी ने मुझे भी हिंदी सेवी सम्मान से उपकृत कर दिया। सो यह पकौड़े खा रहा हूं।' 'मुझे आपके पकौड़ा खाने से गुरेज नहीं है। लेकिन आपने हिंदी के लिए किया क्या है?' मैं हतप्रभ रह गया, अनायास ऐसा प्रश्न सुनकर, फिर साहस कर बोला - 'हिंदी के लिए मेरे जैसा नाचीज कर भी क्या सकता है? बाई दी वे आप हिंदी के लिए क्या कर रहे हैं?' मैंने उनसे पूछा तो वे बिदक गए, बोले — 'हमसे मत पूछिए यह सवाल। हम तीस-चालीस वर्षों से शास्त्री जी के साथ लगे हुए हैं। हिंदी पखोड़े का आगाज करके हमीं उसका समापन करके पूरे साल हिंदी सेवा से लबरेज रहते हैं।' मैंने उन्हें नमस्कार किया और घर लौट आया।

पूरन सरमा

इनसाइड

2030 तक लॉजिस्टिक रैंकिंग में शीर्ष 25 देशों में आ जाएगा भारत

विश्व बैंक की तरफ से जारी लॉजिस्टिक परफॉरमेंस इंडेक्स (एलपीआई) में 38वां स्थान हासिल किया है। 139 देशों की इस रैंकिंग में 2022 की तुलना में भारत की स्थिति में 6 पायदान का सुधार आया है।

नई दिल्ली। इस साल भारत ने विश्व बैंक की तरफ से जारी लॉजिस्टिक परफॉरमेंस इंडेक्स (एलपीआई) में 38वां स्थान हासिल किया है। 139 देशों की इस रैंकिंग में 2022 की तुलना में भारत की स्थिति में 6 पायदान का सुधार आया है। इसे लेकर विश्व बैंक के अधिकारियों से बात चल रही है और उम्मीद है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की बदौलत 2030 तक भारत की एलआईपी रैंकिंग में शीर्ष 25 देशों मे शामिल हो जाएगा।

वाहन डीलर भी शुरू करें स्क्रैपिंग सुविधा: गडकरी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वाहन डीलरों को भी वाहन 'स्क्रैपिंग' सुविधाएं खोलनी चाहिए। पांचवें ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि सरकार सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर रही है। इससे डीलर को वाहन स्क्रैपिंग सुविधा शुरू करने की अनुमति मिलेगी। गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। वाहन डीलर भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मंत्री ने कहा, उनका सपना भारत को दुनिया का शीर्ष वाहन केंद्र बनाना है।

20,000 टन चीनी खरीदेगा नेपाल

नेपाल सरकार घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आगामी त्योहारों से पहले भारत से 20,000 टन चीनी आयात करेगी। नेपाल के उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 60,000 टन चीनी आयात करने के लिए सीमा शुल्क में छूट देने का आग्रह किया था। लेकिन, वित्त मंत्रालय ने फिलहाल 20,000 टन चीनी आयात करने की अनुमति ही दी है। नेपाल सरकार अभी से त्योहारों को लेकर तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता धनीराम शर्मा के मुताबिक, मंत्रालय ने सीमा शुल्क पर 50% की छूट दी है, यानी यह पहले लगाए गए 30% सीमा शुल्क से 15% कम है।

रजनीश कुमार मास्टरकार्ड इंडिया के चेयरमैन बने

एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार मास्टरकार्ड इंडिया के गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। मास्टरकार्ड ने बताया कि रजनीश कुमार स्थानीय नेतृत्व और टीम के साथ घरेलू बाजार में मास्टरकार्ड को बढ़ाने पर फोकस करेंगे।

ऑयल इंडिया करेगी 25,000 करोड़ निवेश

ऑयल इंडिया शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 2040 तक स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट में 25,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। चेयरमैन रंजीत रथ ने कहा, कंपनी ने परिवहन के साथ उद्योगों में प्रदूषण फैलाने वाले तरल ईंधन को बदलने में मदद के लिए अरुणाचल प्रदेश से असम तक प्राकृतिक गैस लाने के लिए 80 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाएगी।

जेट एयरवेज की हवाई उड़ान से क्रैश लैंडिंग तक, कुछ ऐसा रहा अब तक का सफर

परिवहन विशेष

देश की कामयाब एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज एक समय में यह जहां कामयाब एयरलाइन कंपनी है। ऐसे में हमें जरूर समझना चाहिए कि आखिर यह कंपनी अपनी किन गलतियों की वजह से डूब गई है? आपको बता दें कि जेट एयरवेज की आखिरी उड़ान 18 अप्रैल 2019 को हुई थी। आइए कंपनी के सफर के बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। वर्ष 2007 में शुरू हुई जेट एयरवेज का सफर शुरू हुआ था। जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल थे। ऐसा माना जाता है कि एयरलाइन यात्रियों को कम शुल्क में हवाई यात्रा का लुत्फ देता हैं। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी के हालात अब खराब हो गए हैं। एयरलाइन की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से कंपनी के चेयरमैन नरेश गोयल ने इस्तीफा दे दिया है।

कई लोग मानते हैं कि कंपनी के चेयरमैन के कुछ गलत फैसलों की वजह से कंपनी आज कर्ज के तले दब गई है। आपको बता दें कि नरेश गोयल ने सहारा एयरलाइंस को लगभग 1450 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसे एयरलाइन सेक्टर में सबसे बड़ा सौदा माना जाता है। इस डील के बाद कंपनी को फाइनेंशियल, लीगल और एचआर जैसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आइए, जानते हैं कि कंपनी किस कारण की वजह से डूब गई है।

फ्लाइट का साइज

कंपनी ने दक्कन एयरवेज, इंडिगो और स्पाइसजेट को मात देने के लिए सहारा एयरलाइन को खरीदा था। इसके बाद कंपनी ने कई प्लेन का ऑर्डर दे दिया है। ऑर्डर के बाद जो प्लेन आए थे उसमें सीटें काफी कम थी। इस वजह से कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कंपनी के प्लेन में 8 फर्स्ट क्लास की सीटें थी, इन सीटों की कई बार बुकिंग भी नहीं होती है। इस वजह से कई बार प्लेन में काफी जगह रह जाती थी और कम बुकिंग की वजह से कंपनी को घाटा हो रहा था।

नरेश गोयल लेते थे खुद फैसले

कई लोग मानते हैं कि कंपनी के चेयरमैन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भरोसा नहीं करते थे। ऐसे में जेट एयरवेज चलाने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी कोई फैसला नहीं ले पाते थे। कंपनी के सारे फैसले नरेश गोयल ही लेते थे। जब कंपनी कर्ज के बोझ में दबने लग गई थी तो कंपनी के चेयरमैन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स दीपक पारेख से मिले। दीपक द्वारा दिये गए सुझाव को भी नरेश गोयल ने अनसुना कर दिया।

कुछ सालों के बाद टाटा ग्रुप जेट एयरवेज को खरीदने का प्रस्ताव देते हैं। इस प्रस्ताव पर भी नरेश गोयल सहमत नहीं होते हैं। ऐसे में टाटा ग्रुप ने अपने हाथ खींच लिये। इसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी और कर्ज के बोझ में दब गई है।

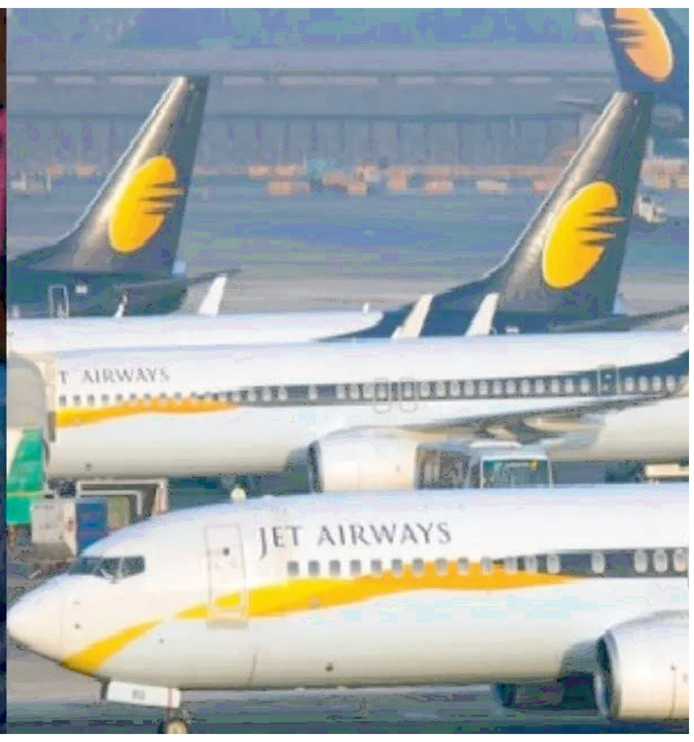

कंपनी के खिलाफ दर्ज हुई FIR

वर्ष नवंबर 2022 में कंपनी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। यह एफआईआर केनरा बैंक के अधिकारियों ने जेट एयरवेज के नरेश गोयल, अनीता गोयल, गौरंग आनंद शेट्टी और कई लोगों पर किया। इसके बाद कंपनी के चेयरमैन को ईडी ने बुलाया था। आज के समय में नरेश गोयल समेत कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी मामला दर्ज किया गया।

जेट एयरवेज का किराया

कंपनी हमेशा से बड़े वर्ग को सुविधा देती है। कंपनी की हवाई टिकट बाकी एयरलाइंस के मुताबिक महंगी थी। यह भी एक वजह थी कि ग्राहक जेट एयरवेज की जगह बाकी एयरलाइन को सिलेक्ट करते थे। ऐसे में कंपनी को एक सीट पर 1 रुपये से 50 पैसे तक का नुकसान का सामना करना पड़ा। इस वजह से कंपनी हर दिन घाटे में पहुंच गई। कंपनी के वित्तीय नुकसान का असर कंपनी के शेयर पर भी देखने को मिला। खबर लिखते वक्त जेट एयरवेज के शेयर (Jetairways Share Price) 53.75 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

जेट एयरवेज पर कितना है कर्ज

कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेट एयरवेज ने 25 बैंकों से कर्ज लिया है। अभी भी कंपनी 8,500 करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ से दबी है। कंपनी ने सहारा एयरलाइंस को खरीदते वक्त कैश में डील की थी। कंपनी ने लीज का किराया नहीं चुकाया उसके बाद जेट एयरवेज 17 अप्रैल 2019 में ग्राउंडेड हो गई। अब कंपनी के चेयरमैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं।

इन राज्यों में बनेंगी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच, वित्त मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी पीठ की स्थापना की जाएगी। इस पीठ के जरिये जीएसटी के मामलों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि देश में किस राज्य में कितनी जीएसटी पीठ की स्थापना की जाएगी?

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की 31 पीठों को अधिसूचित किया है। ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इससे व्यवसायों को तेजी होगी और कई समाधान मिलने में भी मदद करेगा।

आज के समय में कर अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट होने के बाद करदाताओं को उच्च न्यायालयों में जाने की आवश्यकता होती है। यह प्रोसेस में काफी समय लगता है। इसकी वजह यह है कि उच्च न्यायालय पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं। इनके पास जीएसटी मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष पीठ नहीं है।

जीएसटी पीठ की स्थापना

वित्त मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार गुजरात और केंद्रशासित प्रदेशों - दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में जीएसटीएटी की दो पीठें होंगी। वहीं, गोवा और महाराष्ट्र को मिलाकर तीन बेंच होंगी.

इसके अलावा कर्नाटक और राजस्थान में दो-दो बेंच होंगी जबकि उत्तर प्रदेश में तीन बेंच होंगी।

पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुल मिलाकर दो-दो जीएसटीएटी बेंच होंगी जबकि केरल और लक्षद्वीप में एक बेंच होगी।

इसी तरह सात पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में एक पीठ होगी। अन्य सभी राज्यों में जीएसटीएटी की एक पीठ होगी। सरकार पहले चरण में 31 ट्रिब्यूनल अधिसूचित किए हैं जिनका गठन देश के सभी प्रमुख शहरों में किया जाएगा।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा

कर विवादों को संबोधित करने के लिए एक निष्पक्ष, विशेषज्ञ और कुशल मंच प्रदान करने में उनके महत्व के कारण कर मामलों को हल करने के लिए जीएसटी न्यायाधिकरण आवश्यक हैं। वे कर प्रशासन में निष्पक्षता, जवाबदेही और कानून का शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब, न्यायाधिकरणों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने, योग्य सदस्यों की नियुक्ति और आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधन उपलब्ध कराने का अगला चरण शुरू होगा।

देशभर में पेट्रोल-डीजल के नए रेट्स जारी, जानिए क्या आपके शहर में बदले दाम

देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को अपडेट कर दिया गया है। आज भी इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी चालक को आज भी राहत है। देश की राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96 .72 रुपये और डीजल 89 .62 रुपये प्रति लीटर है। आइए जानतें हैं कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल की क्या कीमत है?

नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को जारी करते हैं। यह कीमतें वैश्विक कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड रेट के आधार पर तय किया जाता है। इन कीमतों में कई तरह के टैक्स और कमीशन भी जुड़े होते हैं। इस वजह से हर राज्य में इसकी कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है। पूरे देश में एक साल से इनकी कीमतों को स्थिर रखा गया है। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड का रेट 90.53 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड का भाव 90.74 डॉलर हो गया है।

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल-डीजल की कीमत

दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 92.76 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 94.27 रुपये है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।

नोएडा, जयपुर और बाकी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

नोएडाः पेट्रोल 97.00 रुपये और डीजल 90.14 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्रामः पेट्रोल 96.84 रुपये और डीजल 89.72 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरुः पेट्रोल 101.94 रुपये और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़ः पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर

हैदराबादः पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर

जयपुरः पेट्रोल 108.45 रुपये और डीजल 93.69 रुपये प्रति लीटर

पटनाः पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर

लखनऊः पेट्रोल 96.47 रुपये और डीजल 89.66 रुपये प्रति लीटर

कैसे चेक करें पेट्रोल-डीजल के दाम

अगर आप शहर से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इनकी कीमतों को जरूर चेक करना चाहिए। आप एक मैसेज या फिर ऐप्स के जरिये भी इनकी कीमतों को चेक कर सकते हैं। आप इंडियन ऑयल के ऐप्स के जरिये भी किसी भी शहर के ताजा रेट्स जान सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल के ग्राहक RSP डीलर कोड लिखकर 92249 92249 पर मैसेज करके भी दाम जान सकते हैं।

डॉलर के मुकाबले रुपया खुला सपाट, 83.02 पर कर रहा है कारोबार

शेयर बाजार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया सीमित दायरे में कारोबार में कारोबार कर रहा है। विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ें जारी होने के बाद डॉलर मजबूत हुआ। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने भी रुपये को प्रभावित किया है।

नई दिल्ली। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में सीमित दायरे में कारोबार देखा गया। वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मजबूत अमेरिकी मुद्रा से सकारात्मक घरेलू इक्विटी के समर्थन को नकार दिया गया।

विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रास्फीति संख्या जारी होने के बाद डॉलर मजबूत हुआ, जो उम्मीद से अधिक बताया गया और घरेलू इकाई पर इसका असर पड़ा। हालाँकि, घरेलू इक्विटी में तेजी का रुझान, जिसमें दोनों बेंचमार्क सूचकांक अब तक के उच्चतम स्तर को छू रहे हैं, ने रुपये को निचले स्तर पर समर्थन दिया।

रुपया हुआ सपाट

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। यह डॉलर के मुकाबले 83.02 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 83.07 के निचले स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद से 4 पैसे कम है।

गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे गिरकर 83.03 पर बंद हुआ।

विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के और बढ़ने की उम्मीद के कारण रुपये में मामूली नकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ कारोबार होने की संभावना है। इसके अलावा, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली का दबाव रुपये पर और दबाव डाल सकता है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी हस्तक्षेप और सकारात्मक घरेलू बाजारों से रुपये को निचले स्तर पर समर्थन मिल सकता है। इस बीच डॉलर इंडेक्स 0.15 फीसदी गिरकर 105.28 पर आ गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.95 प्रतिशत बढ़कर 94.59 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

शेयर बाजार में तेजी

आज बीएसई सेंसेक्स 102.84 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 67,621.84 पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी 30.25 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 20,133.35 पर था। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) गुरुवार को 294.69 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

अगस्त में 22.8 प्रतिशत बढ़कर घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या हुई 1.24 करोड़, डीजीसीए ने जारी किए आंकड़े

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने आज आंकड़े जारी कर बताया कि इस साल अगस्त में घरेलू हवाई यात्री यातायात में 22.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। डीजीसीए के मुताबिक इस साल अगस्त में यात्रियों की संख्या बढ़कर 1.24 करोड़ हो गई जो पिछले साल की समान अवधि में 1.01 करोड़ थी। आंकड़ों के मुताबिक इंडिगो ने सबसे ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक छोड़ा।

नई दिल्ली। हर गुजरते महीने के साथ घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के आज आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस साल अगस्त में घरेलू हवाई यात्री यातायात 22.81 प्रतिशत बढ़ा। डीजीसीए ने बताया कि यात्रियों की संख्या इस साल अगस्त में बढ़कर 1.24 करोड़ हो गई है जो एक साल पहले की इसी अवधि में 1.01 करोड़ था।

किस एयरलाइन ने कितने यात्रियों ने की यात्रा?

डीजीसीए ने कहा कि बजट एयरलाइन कंपनी इंडिगो से सबसे ज्यादा यात्रियों ने यात्रा किया। आंकड़ो के मुताबिक अगस्त में 78.67 लाख यात्रियों को इंडिगो ने उनके मंजिल तक पहुंचाया। यह संख्या कुल घरेलू यात्री मात्रा का 63.3 प्रतिशत हिस्सा है।

टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने 12.12 लाख यात्री और टाटा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी AIX कनेक्ट (पूर्व में एयरएशिया इंडिया) ने अगस्त के दौरान 9.78 लाख यात्रियों को पहुंचाया।

अगस्त में एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी 9.8 प्रतिशत थी जबकि AIX कनेक्ट की 7.1 प्रतिशत थी। आपको बता दें कि पिछले महीने में ही एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और नए पोशाक को लॉन्च किया था। नई रीब्रांडेड एयर इंडिया के प्लेन दिसंबर से दिखना शुरू होंगे।

विस्तारा एयरलाइन, जिसमें टाटा संस की 51 प्रतिशत और सिंगापुर एयरलाइंस की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ने 9.8 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ 12.17 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। डीजीसीए ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि अगर एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया को मिला दें तो इन तीनों ने पिछले महीने कुल मिलाकर 33.07 लाख यात्रियों को यात्रा कराई।

ऑन टाइम परफॉर्मेंस में इंडिगो ने किया टॉप

विस्तारा ने पिछले महीने के दौरान सभी घरेलू एयरलाइनों के बीच सबसे अधिक लोड फैक्टर 91.3 प्रतिशत दर्ज किया। पिछले महीने के दौरान चार प्रमुख हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से आने और जाने वाली अपनी 89 प्रतिशत उड़ानों के साथ इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस सबसे अधिक रहा।

चिटफंड पैसा जमाकर्ताओ को कब मिलेगा न्याय

भुवनेश्वर। चिटफंड आयोग कार्यालय में जमाकर्ताओं की फाइल सड़ रही है. पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले हजारों जमाकर्ताओं की फाइलों में पेड़ उग आए हैं और फूल खिल गए हैं। कटक पुलिस लाइन स्थित जस्टिस एमएम दास चिटफंड कमीशन के कार्यालय में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं. इसमें चिटफंड जांच आयोग को 10 साल पूरे हो गये हैं. लेकिन चिटफंड जमाकर्ताओं की उम्मीद जस्टिस एमएम आयोग के दफ्तर में लटकी हुई है. जमाकर्ता का रिकॉर्ड पत्र और सच्चा पाठ। इसके रख-रखाव के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. 9 जुलाई 2013 को सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की. रिकॉर्ड के मुताबिक, इस जांच प्रक्रिया में 6 करोड़ 19 लाख से ज्यादा खर्च हुए हैं. राज्य सरकार ने जमाकर्ताओं के लिए 300 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की भी घोषणा की। यहां तक कि गरीब जमाकर्ताओं को भी फंड से कोई पैसा नहीं मिला। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. हजारों करोड़ की धोखाधड़ी के सबूत सामने आए हैं।

गौभक्त महाकुंभ के न्यौता में पीले चावल बांटे

भीलवाड़ा। गौवंश बचाओं संघर्ष समिति द्वारा 17 सितम्बर रविवार को किए जा रहे गौ-भक्त महाकुम्भ में आज शुभ समय पर ध्वजारोहण किया गया और सभी गौ-भक्तों को पीले चावल देकर निमंत्रण दिया गया। शहर के सभी मन्दिरों के पुजारियो को दुपट्टा ओढ़ाकर निमंत्रण पत्र देकर महाकुम्भ में पधारने का न्यौता दिया गया। संघर्ष समिति के संयोजक बृजराज कृष्ण उपाध्याय ने बताया कि गौ वंश की हत्या बंद करवाने को लेकर 17 सितम्बर को यज्ञ, छप्पन भोग व महाप्रसादी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शहर व जिले के सभी संतगण व गौ भक्त उपस्थित होगें तथा सरकार को मांग पत्र भेजा जायेगा।

सोफ़िया इंटरनेशनल स्कूल ने सदर को हराकर किया ट्रॉफी पर कब्जा

एसडी गौतम, नागल। जनपद स्तर पर इस्लामिया इंटर कॉलेज देवबंद में आयोजित हुई वॉलीबॉल प्रतियोगिता में देवबन्द तहसील की ओर से खेलते हुए सोफिया की टीम ने सेमी फाइनल मैच में रामपुर को हराकर फाइनल में जगह बनाई। साथ ही प्रतियोगिता के फ़ाइनल मुक़ाबले में तहसील देवबंद की ओर से खेलते हुए सहारनपुर सदर को हराकर जनपद स्तर पर प्रतियोगिता ट्रॉफी देवबंद तहसील के नाम की। सोफिया इंटरनेशनल स्कूल से बालक वर्ग अंडर 19 में कक्षा दस के छात्र आशु को मुज़फ्फरनगर में मण्डल स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में चयनित किया गया। तो अंडर 14 में वासु और अनंत का चयन हुआ है। इस मौक़े पर स्कूल निर्देशक कोणार्क चौधरी व प्रधानाचार्य आशीष कुमार शर्मा ने स्कूल के कोच प्रवेश सैनी एवं सभी छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण अंचल के बच्चे जिले स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे जो उनके और विद्यालय के लिए गर्व की बात है।

गृह निर्माण समितियों से आदर्श उप विधियां लागू करने की अपील

भोपाल। उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा बताया गया कि भोपाल जिले की सभी गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं पर शासन की आदर्श उप विधियां लागू की गई है जिन्हें सभी संस्थाओं को अंगीकृत करना है। उन्होंने बताया कि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष, प्रबंधक एवं प्रशासकों को सूचित किया जाता है कि संबंधित गृह निर्माण सहकारी संस्था के मॉडल बायलॉज कार्यालय के पंजीयन कक्ष से 15 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से सायं 3 बजे तक प्राप्त कर सकते है।

अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे बिजली बिल भुगतान केन्द्र

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सितम्बर माह में 16,23,30 (सभी शनिवार), 17,24 सितम्बर (सभी रविवार), 19 सितम्बर (गणेश चतुर्थी) एवं 28 सितम्बर (मिलाद-उन-नबी/अनंत चतुर्दशी) को बिजली बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल आफिस में आईसेक्ट (AISECT) कियोस्क के माध्यम से कैश के जरिए बिल भुगतान तथा ऑनलाइन माध्यम से भी बिल भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केन्द्र/बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है।

'आम लोगों की आवाज सुनता है सुप्रीम कोर्ट'

सीजेआई बोले- अनुच्छेद 370 पर देश की ही बात सुनी

सीजेआई ने कहा कि संविधान पीठ के मामलों में संविधान की व्याख्या की जाती है, जो देश में लीगल फ्रेमवर्क का आधार बनते हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आम नागरिकों से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राष्ट्र की आवाज सुन रहे हैं और अनुच्छेद 370 पर हुई सुनवाई इसका सबूत है।

दरअसल वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा ने आरोप लगाया है कि सर्वोच्च अदालत सिर्फ संविधान पीठ के मामलों पर सुनवाई कर रही है, जिनमें आम जनता का कोई हित नहीं होता और सामान्य नागरिकों के मामलों पर सुनवाई नहीं कर रही है। मैथ्यूज नेदुम्पारा ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे एक ईमेल में यह आरोप लगाए हैं। दरअसल नेदुम्पारा एक एमएसएमई फर्म का मामला लेकर कोर्ट में पेश हुए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि पहले हाईकोर्ट में जाइए। इसके बाद नेदुम्पारा ने ईमेल भेजकर उक्त आरोप लगाए।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नेदुम्पारा के ईमेल के जवाब में कहा कि संविधान पीठ के मामले भी आम जनता से जुड़े होते हैं। सीजेआई ने कहा कि 'मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आप संविधान पीठ के मामलों के बारे में नहीं जानते हैं और शायद आपको इनकी समझ भी नहीं है। संविधान पीठ के मामलों में संविधान की व्याख्या की जाती है, जो देश में लीगल फ्रेमवर्क का आधार बनते हैं।'

सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 370 का मामला भी आम जनता से जुड़ा मामला था। हमने कई नागरिक संगठनों और लोगों की बात सुनी तो हम देश की आवाज सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और पांच सितंबर को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजेआई ने ये भी कहा कि बीती 13 सितंबर को हमने संविधान पीठ के ऐसे मामले पर सुनवाई की, जिससे देश में असंख्य ड्राइवरों की

कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी, आतंक फैलाने की साजिश के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को आईएसआईएस झारखंड मॉड्यूल मामले में बहु-राज्यीय कार्रवाई में नौ स्थानों पर छापे मारे और क्षेत्र में आतंक फैलाने की साजिश में कथित भूमिका के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को आईएसआईएस झारखंड मॉड्यूल मामले में बहु-राज्यीय कार्रवाई में नौ स्थानों पर छापे मारे और क्षेत्र में आतंक फैलाने की साजिश में कथित भूमिका के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने कहा कि यह मामला आईएसआईएस मॉड्यूल से संबंधित है, जिसका खुलासा इस साल जुलाई में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के एक छात्र की गिरफ्तारी के साथ हुआ था। छात्र फैजान एएमयू परिसर के पास रहने के दौरान आईएसआईएस से जुड़े कट्टरपंथी व्यक्तियों के संपर्क में आया था। एनआईए ने बताया कि बिहार के सीवान जिले, उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और महाराजगंज जिलों, मध्य प्रदेश के रतलाम, पंजाब के लुधियाना, गोवा के दक्षिण गोवा, कर्नाटक के यादगीर और महाराष्ट्र के मुंबई में छापे मारे गए। उमर (23 वर्षीय) को आतंकी साजिश में सक्रिय भूमिका के लिए रतलाम से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कट्टरपंथ के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आईएसआईएस के प्रचार-प्रसार और आतंकवाद से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भोले-भाले युवाओं की भर्ती शामिल थी।

लखीमपुर खीरी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी नैट परीक्षा केंद्र पर दूसरे स्कूल के शिक्षक बनेंगे पर्यवेक्षक

जिला स्तरीय अधिकारियों के सुपरविजन में संपन्न होगी नैट परीक्षा। बेसिक और केजीबीवी में कक्षा 1 से 3 के बच्चों की होगी नैट परीक्षा

परिवहन विशेष न्यूज

लखीमपुर खीरी। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विभाग के स्तर से नेट (निपुण असेसमेंट टेस्ट) होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि जनपद खीरी में नैट परीक्षा 15 एवं 21 सितंबर 2023 को परिषदीय स्कूलों में ही आयोजित होगी। ज्ञातव्य है कि यह नैट परीक्षा 11 व 12 सितंबर को आयोजित होनी थी परंतु ख़राब मौसम और अतिवृष्टि के कारण यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अब राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा 15 एवं 21 सितम्बर 2023 को परीक्षा कराने के लिए आदेशित किया गया है।परीक्षा शांतिऔर शुचितापूर्वक कराने के लिए दूसरे स्कूल के शिक्षकों को परीक्षा केंद्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है।

जनपद के 2700 परिषदीय स्कूलों और 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक पढ़ने वाले करीब 193869 छात्र-छात्राएं परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। इनमें से 1973 प्राथमिक, 727 कंपोजिट स्कूलों और 16 केजीबीवी में परीक्षा होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि छात्र परीक्षा ओएमआर शीट पर देंगे ओएमआर और प्रश्न पत्र राज्य परियोजना कार्यालय से उपलब्ध कराए गए हैं। परीक्षा पर नजर रखने के लिए जिलाधिकारी महोदय श्री महेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा जिला स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गयी है। नेट परीक्षा के सफल संपादन हेतु जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, कोर कमेटी और सचल दस्ते बनाए गए हैं। इन तिथियों में होगी नेट परीक्षा- 15 सितंबर - कक्षा 1 से 3 की नैट परीक्षा।

21 सितंबर - कक्षा 4 से 8 की नैट परीक्षा परिषदीय स्कूलों और केजीबीवी में शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए नैट परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा परिणाम के आधार पर स्कूलों के शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, जिला समन्वयको, एसआरजी, एआरपी, शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया है कि परीक्षा को शुचिता पूर्वक संपन्न कराएं। बच्चों की शत प्रतिशत प्रतिभागिता सुनिश्चित हो।

राहुल नवीन लेंगे एसके मिश्रा की जगह, ईडी के प्रभारी निदेशक नियुक्त; जानें उनके बारे में सबकुछ

नई दिल्ली। ईडी में नए निदेशक की नियुक्ति होने तक राहुल लगातार चर्चा में रही इस महत्वपूर्ण एजेंसी का नेतृत्व करेंगे। बिहार के रहने वाले राहुल नवीन अपने कुशल व शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं।

भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 1993 बैच के वरिष्ठ अधिकारी राहुल नवीन को ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ईडी के मौजूदा निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर को समाप्त गया। उन्होंने लगभग चार साल 10 महीने तक ईडी निदेशक के रूप में काम किया। उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए सीवीसी अधिनियम में संशोधन भी किया गया था।

कौन हैं राहुल नवीन?

ईडी में नए निदेशक की नियुक्ति होने तक राहुल लगातार चर्चा में रही इस महत्वपूर्ण एजेंसी का नेतृत्व करेंगे। बिहार के रहने वाले राहुल नवीन अपने कुशल व शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में जांच एजेंसी में कहा जाता है कि वह बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनकी कलम बहुत चलती है। कानूनी तरीके से काम करने के साथ ही बहुत सुलझे हुए हैं। राहुल नवीन की गिनती ईडी के तेज-तर्रार अधिकारियों में की जाती है। नवीन कार्यकारी निदेशक के अलावा ईडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हटाए गए मिश्रा

ईडी के निवर्तमान निदेशक संजय मिश्रा को कार्यकाल विस्तार देने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। हालांकि केंद्र के अनुरोध पर मिश्रा को 15 सितंबर तक पद पर रहने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में सरकार के पास नए अधिकारी को इस एजेंसी के प्रमुख पद पर लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था।

दो दिवसीय इंजीनियर्स डे कार्यक्रम टेक–कृति का समापन, इंजीनियर्स को किया सम्मानित

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय में इंजीनियर्स डे पर दो दिवसीय कार्यक्रम 'टेक कृति' का समापन इंजीनियर विभाग के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति तथा विजेता को सम्मानित करके किया गया। समापन कार्यक्रम में स्कूल आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विभाग के डीन प्रोफेसर आर के सोमानी ने सभी अतिथियों ,इंजीनियर तथा छात्र छात्राओं का स्वागत किया।डेप्युटी डीन इंजीनियरिंग प्रो अर्चना अग्रवाल ने दो दिन के आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा को बताया।डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर प्रो विनेश अग्रवाल ने भारत रत्न ने सर एम विश्वेश्वर्या की जीवनी को बताया।प्रो राकेश भंडारी ने इस वर्ष कि थीम इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलपमेंट पर अपने विचार रखे।रजिस्ट्रार प्रो राजीव मेहता ने विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग की उपलब्धियों को बताया। प्रो प्रेसिडेंट प्रोफेसर मानस रंजन ने इंजीनियरिंग विभाग को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएसएल के इंजीनियर अतुल शाह, एंटरप्रेनियर एस के चोरड़िया को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में उत्कृष्ठ कार्य के लिए गौरव चतुर्वेदी, महावीर असरवा, आलोक पंवार को सम्मानित किया गया। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने फ्यूचर के सभी इंजीनियरिंग छात्रों को सफलता के टिप्स दिए तथा इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाया।दो दिन के कार्यक्रम में प्रथम द्वितीय रहे छात्र छात्राओं को अवार्ड के साथ अमित किया गया। टेक कृति कार्यक्रम के समन्वयक फैकल्टी अदिति तुलछीया, कल्पित जैन ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विभिन्न संकाय के फैकल्टी स्टाफ आदि उपस्थित थे।जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया की इंजीनियर्स एसोसिएशन एंड वेलफेयर सोसायटी की तरफ से टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में संगम विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति दी।

सहारनपुर पोर्टल पर एक माह से लम्बित शिकायत का जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान

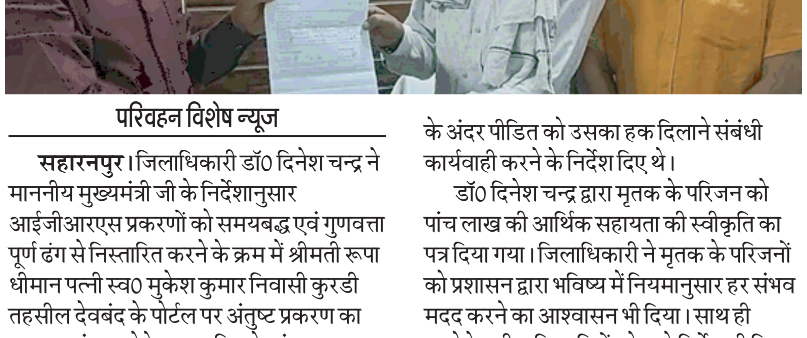

परिवहन विशेष न्यूज

सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आईजीआरएस प्रकरणों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारित करने के क्रम में श्रीमती रूपा धीमान पत्नी स्व0 मुकेश कुमार निवासी कुरडी तहसील देवबंद के पोर्टल पर अंतुष्ट प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए 02 दिन के अंदर निस्तारित कराकर संबंधित को उनका हक दिलाया। ज्ञातव्य है कि मुकेश कुमार भायला फीडर पर तैनात थे। उनकी 11 मई को असामयिक मृत्यु हो गयी थी। उनके परिवार को वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु उनकी पत्नी श्रीमती रूपा धीमान ने पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। जो लगभग एक माह से लंबित थी। जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक में प्रकरण संज्ञान आने पर प्रकरण का निस्तारण समय से न करने पर कडी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियन्ता को तीन दिन के अंदर पीडित को उसका हक दिलाने संबंधी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।

डॉ0 दिनेश चन्द्र द्वारा मृतक के परिजन को पांच लाख की आर्थिक सहायता की स्वीकृति का पत्र दिया गया। जिलाधिकारी ने मृतक के परिजनों को प्रशासन द्वारा भविष्य में नियमानुसार हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होने सभी अधिकारियों को कडे निर्देश भी दिए कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करना सुनिश्चित करें। शिकायत का अंतिम रूप से निस्तारण तभी माना जाए जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो। उन्होने कहा कि आईआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से न लेने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। आमजन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की उच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर दी जानकारी

नागल। अग्रणी शिक्षण संस्था इंद्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी परिसर सहारनपुर में हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के चेयरमैन डॉ० एससी कुलश्रेष्ठ ने हिंदी दिवस के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था की प्राचार्या डॉ० अंजू वालिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विचार रखते हुए प्राचार्य डॉ० अंजू वालिया ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जोकि देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है परंतु देश में सर्वाधिक हिंदी भाषा ही प्रयोग में लाई जाती है। मंच संचालन करते हुए डॉ० कमल कृष्ण ने सुंदर कविता प्रस्तुत कर हिंदी भाषा के इतिहास एवं समृद्धि पर प्रकाश डालते हुए विस्तृतपूर्वक जानकारी प्रदान की। इस मौके पर छात्रों हेतु निबंध, वाद विवाद एवं भाषण समेत विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें संस्था के छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभाग करने वाले छात्रों को संस्था की प्राचार्य डॉ० अंजू वालिया ने उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अमित परमार ने किया। इस दौरान उपनिदेशक आशुतोष गुप्ता, डॉ० नेहा त्यागी, उदित चौहान, छवि त्यागी, कल्पना शर्मा, राहुल, सचिन, सूर्यकांत, वीएस कुशवाहा, अंजूलिका, भारती समेत आदि संस्था स्टाफ उपस्थित रहा।

मतदाताओं के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर 180023301950 स्थापित

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश ने मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर 180023301950 है। किसी भी प्रकार जानकारी, सहायता एवं शिकायत के लिए मतदाता कार्यालयीन समय पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। टोल फ्री नंबर के माध्यम से मतदाताओं की समस्या का त्वरित निदान किया जाएगा। राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में 1950 के कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। मतदाता 1950 पर कॉल कर निर्वाचन से जुड़ी कोई भी जानकारी, शिकायत जिले में ही दर्ज करा सकते हैं। जिला स्तर पर ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक जिले से यदि कोई मतदाता दूसरे जिले के कॉल सेंटर पर फोन करते हैं तो उन्हें 1950 के आगे संबंधित जिले का एसटीडी कोड लगाना होगा। जिले में स्थापित किए गए कॉल सेंटरों की मुख्यालय स्तर से निगरानी भी की जा रही है।

भारतीय सेना के जवानों का एक छोटा सा अनुरोध:- पानी की खरीदारी करते समय "सेना जल" (सेना जल) की मांग करें

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। बिसलेरी और एक्वाफिना विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित है और इनका पानी खरीदने में हम जो पैसा खर्च करते हैं वह भारत से दूसरे देशों में चला जाता है।

भारतीय सेना के जवानों का एक छोटा सा अनुरोध है:- यात्रा करते समय या खरीदारी करते समय 'सेना जल' (सेना जल) की मांग करें। यह सेना जल (सेना जल) लगभग सभी स्थानों पर (यहां तक कि थोक में भी) उपलब्ध है। भारतीय सेना की आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने SENA JAL की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत जनरल विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत ने की है। यह पैक आधा लीटर और एक लीटर के पैक में उपलब्ध है।

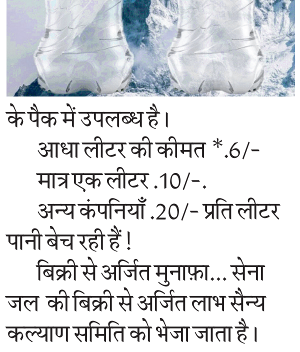

आधा लीटर की कीमत *.6/-

मात्र एक लीटर .10/-.

अन्य कंपनियाँ .20/- प्रति लीटर पानी बेच रही हैं!

बिक्री से अर्जित मुनाफ़ा... सेना जल की बिक्री से अर्जित लाभ सैन्य कल्याण समिति को भेजा जाता है।

इस पैसे का उपयोग शहीद सैनिकों के परिवारों और उनके बच्चों की शिक्षा पर किया जाता है!

सेना जल (सेना जल) का निर्माण भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, इसलिए टेलीविजन या किसी मीडिया द्वारा कोई समाचार या प्रचार नहीं किया जाता है।

सेना जल को कम दर पर बेचने का यह एक कारण है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं क्योंकि कोई प्रचार-प्रसार नहीं होता है!

जब भी आप पैक्ड पीने का पानी खरीदना चाहें, तो दुकान विक्रेता से सेना जल (सेना जल) मांगें! यदि हमें अपने राष्ट्र और सेना पर गर्व है तो इस संदेश को हर जगह पहुचाकर सेना के लिए व्यापक रूप से साझा करें!

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959. (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023